▪ RNI No. 58061/93 ▪ वर्ष - 21 ▪ अंक - 136 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- बेंगलूरु » बुधवार » 10-12-2025 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 जुनून और जोश के बिना खिलाड़ी के तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते : तेंदुलकर

6 गोवा का नाइट क्लब लाक्षागृह कैसे बन गया?

7 यहां कोई रोडमैप नहीं, रोलरकोस्टर है : प्राजक्ता कोली

फर्स्ट टेक

दिल्ली विस्फोट मामले में आठवां आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के नजदीक एक कार में हुए विस्फोट के सिलसिले में आठवीं गिरफ्तारी की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला जम्मू-कश्मीर के बारामूला का निवासी है और उसे राष्ट्रीय राजधानी से गिरफ्तार किया गया। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने जांच के दौरान 10 नवंबर को लाल किला क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के पीछे की साजिश में बिलाल की संलिप्तता पाई है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। एनआईए की जांच के अनुसार, ''एनआईए की जांच के अनुसार, बिलाल ने जानबूझकर मृत आरोपी उमर उन नबी को आश्रय दिया और उसे लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की। उस पर आतंकवादी हमले से संबंधित सबूत नष्ट करने का भी आरोप है।

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने सूडानी मिलिशिया नेता को 20 साल की सजा सुनाई

द हेग/एपी। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीशों ने मंगलवार को खूंखार सूडानी जंजावीद मिलिशिया के एक नेता को 20 साल से भी अधिक समय पहले दारफुर में हुए विनाशकारी संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। पिछले महीने एक सुनवाई में अभियोजकों ने अली मुहम्मद अली अब्द-अल-रहमान को आजीवन कारावास की सजा देने का अनुरोध किया था। अली मुहम्मद को अक्टूबर में युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के 27 मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 2003-2004 में सामूहिक रूप से फांसी का आदेश देना और दो कैदियों को कुल्हाड़ी से हमला करके मार डालना शामिल था।

कराची में हिंदू महिला और उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण

कराची/भाषा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू महिला और उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात बंदूकधारियों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटना शनिवार को कराची के शेरशाह स्थित सिंधी मोहल्ले में घटी। परिवार द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला को तीन हथियारबंद व्यक्तियों ने घर से बाहर निकलते ही जबरन एक सफेद कार में बैठा लिया। इस मामले से स्थानीय समुदाय में भय और चिंता व्याप्त हो गई है।

10-12-2025 सूर्यास्त 5:53 बजे | 11-12-2025 सूर्योदय 6:31 बजे

BSE	NSE
84,666.28	25,839.65
(-436.41)	(-120.90)

सोना	चांदी
13,328 रु.	189,364 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

बेमेल मिलन

मिल जाए स्थिर सरकार अगर,
गठबंधन को भी सह लेंगे।
वर्ना दुर्भाग्य समझ करके,
जैसे-तैसे बस रह लेंगे।
इतिहास गवाही देता है,
संभवतः जल्दी ढह लेंगे।
बेमेल मिलन कब हुए सफल,
बस कथा पुरानी कह लेंगे।।

प्रधानमंत्री ने राजग सांसदों से कहा

कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए, असुविधा के लिए नहीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्राथमिकता लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि कानून या नियम आम लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए और उनकी वजह से किसी निर्दोष भारतीय को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश अब पूरी तरह ''रिफॉर्म एक्सप्रेस'' के दौर में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट मंशा के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सुधार सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजस्व पर केंद्रित नहीं है, ये पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सरकार का लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां दूर करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें।

बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को ''बहुत अच्छे दिशानिर्देश'' दिए और यह संदेश दिया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा मुद्दा रिफॉर्म एक्सप्रेस है। इस बैठक में राजग के सभी सांसद शामिल हुए।

रीजीजू ने कहा, ''मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' चल पड़ी है और अब यह रुकेगी नहीं। यह सुधार देश के हर नागरिक की जिंदगी बदलने के लिए है। जब हम सुधार की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे आर्थिक सुधार समझते हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ प्रशासनिक या सांस्कृतिक सुधार। लेकिन 'सुधार' का असली मतलब है- हर नागरिक के जीवन में बेहतरी है।

भारतीय कारीगरों को विशिष्ट जीआई टैग हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए : मुर्मू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि भारतीय शिल्पकारों ने अपने ज्ञान, समर्पण और कड़ी मेहनत से अपनी वैश्विक पहचान स्थापित की है तथा अब उन्हें अपने उत्पादों के लिए एक विशिष्ट जीआई (भौगोलिक संकेत) टैग प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मुर्मू ने यहां 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि यह जीआई टैग अब भारतीय शिल्पकारों के उत्पादों की पहचान और विश्वसनीयता को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा, मैं इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध करती हूं कि वे अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। इससे आपके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी तथा आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी।

इसके अलावा, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल जैसी योजनाएं भी भारत के क्षेत्रीय हस्तशिल्प उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूत कर रही हैं।

जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिह्न है जो किसी उत्पाद को किसी विशिष्ट स्थान से उत्पन्न होने वाले, उस स्थान से जुड़े अद्वितीय गुणों, प्रतिष्ठा या विशेषताओं से युक्त बताता है। यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय विविधता पर प्रकाश डालता है।

'आइडिया ऑफ इंडिया' को नष्ट कर रही है भाजपा : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को 'वोट चोरी' को ''सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य'' करार दिया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निर्वाचन आयोग पर कब्जा करके इस कृत्य को अंजाम देते हुए 'आइडिया ऑफ इंडिया' (भारत की अवधारणा) नष्ट कर रही है।

उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान वर्ष 2023 के निर्वाचन कानून का उल्लेख करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस कानून में ''पूर्वव्यापी प्रभाव'' से संशोधन किया जाएगा तथा चुनाव आयुक्तों को कठघरे में लिया जाएगा।

उनका यह भी कहना था कि वर्ष 2023 के इस कानून को बदलने की जरूरत है क्योंकि यह निर्वाचन आयुक्तों को ''यह ताकत देता है कि वे जो चाहें करें''। उन्होंने कहा कि इसकी चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' के तहत तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

जय अनमोल अंबानी के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों में अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह की कंपनियों 'रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड' (आरएचएफएल) और 'रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड' के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज कीं, जिनमें से एक में जय अनमोल अनिल अंबानी को नामजद किया गया है और 14,852 करोड़ रुपये की कथित ऋण चूक को जांच के दायरे में लाया गया है। उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, सीबीआई की टीम ने मुंबई के कफ परेड में अनिल अंबानी के घर 'सी विंड' इमारत की सातवीं मंजिल पर स्थित उनके आवास की तलाशी ली।

घुमंतू जातियों की भावी पीढ़ियों की शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं सांसद

नई दिल्ली/भाषा। घुमंतू और बंजारा समुदाय के लोगों के कल्याण के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में इन समुदायों के डेरों के पास शिविर लगाने चाहिए जिससे इनकी भावी पीढ़ियों को शिक्षित किया जा सके। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदाय (डीएनटी) के कल्याण से संबंधित पूरक प्रश्न पूछे जाने के दौरान बिरला ने यह बात कही।

शिवसेना (उबाठा) के भाऊसाहेब वाकचौरे के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू (डीएनटी) समुदाय के कल्याण के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ-साथ इस समुदाय के रहन-सहन पर प्रभाव पड़ा है तथा हमारे आधुनिकता की ओर बढ़ने के साथ इस समुदाय के लोगों के परंपरागत काम बंद होते गए। मंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 फरवरी 2019 को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इन समुदायों के विकास एवं कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात समेत सात राज्यों में डीएनटी समुदाय के लोगों को जाति प्रमाणपत्र जारी किये जा रहे हैं तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की बैठकों में बाकी राज्यों से भी इस संबंध में अनुरोध किये जा रहे हैं।

इंडिगो की उड़ान कार्यक्रम में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश

विमानन मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया

मुंबई/भाषा। नागर विमानन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि इंडिगो को अपनी उड़ान समय-सारणी में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया है। ऐसा करने से संकटग्रस्त एयरलाइन को अपना संचालन स्थिर करने में मदद मिलेगी।

नये उड़ान सेवा नियमों के दूसरे चरण लागू होने के बाद इंडिगो के परिचालन में भारी अव्यवस्था हुई है। इस दौरान 4,000 से अधिक उड़ानें निरस्त की गईं जबकि सैकड़ों उड़ानें देर से संचालित हुईं।

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने एक बयान में कहा कि इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में तलब किया गया था, ताकि वह स्थिति की जानकारी दे सकें। उन्होंने बताया कि एल्बर्स ने छह दिसंबर तक प्रभावित हुई उड़ानों के 100 प्रतिशत रिफंड पूरे कर लिए जाने की पुष्टि की।

नायडू ने कहा, ''इंडिगो के उड़ान कार्यक्रम में 10 प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया गया है। इसके अनुरूप चलते हुए भी इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों तक उड़ानें संचालित करती रहेगी।''

इस मुलाकात के पहले विमान सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने एक आदेश जारी कर कहा था कि इंडिगो की उड़ान समय-सारणी में पांच प्रतिशत कटौती की जा रही है।

नायडू ने कहा कि मंत्रालय को इंडिगो के कुल उड़ान मार्गों में कटौती जरूरी लगती है क्योंकि इससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और रद्दीकरण को घटाने में मदद मिलेगी।

यूरोप का समर्थन जुटाने पर जेलेंस्की का जोर, रूस को क्षेत्र सौंपने से इनकार किया

रोम/एपी। रूस के साथ समझौते के लिए बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है।

यूक्रेन के लिए यूरोपीय समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे जेलेंस्की ने कहा, ''निस्संदेह, रूस इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि हम अपने क्षेत्र उसे सौंप दें। ज़ाहिर है, हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। हम इसी के लिए लड़ रहे हैं।''

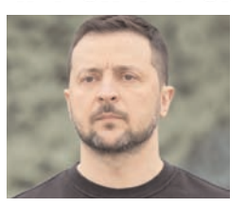

जेलेंस्की ने सोमवार देर रात व्हाट्सएप पर संवाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ''क्या हम कोई क्षेत्र छोड़ने पर विचार कर रहे हैं? क़ानून के अनुसार, हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यूक्रेन के क़ानून, हमारे संविधान, अंतरराष्ट्रीय क़ानून और, सच कहूं तो, हमारे पास नैतिक अधिकार भी नहीं है।''

वहीं, 'पोलिटिको' के साथ एक साक्षात्कार में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ज़ेलेंस्की पर अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला कि यूक्रेन रूस को अपना क्षेत्र सौंप दे।

कांग्रेस ने कई पूर्व निर्वाचन आयुक्तों को राज्यपाल और मंत्री बनाया : निशिकांत दुबे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने कई पूर्व निर्वाचन आयुक्तों को राज्यपाल और मंत्री बनाया, लेकिन अब वह निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता की बात कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर संस्थाओं को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का उल्लेख है लेकिन ''आश्चर्य है कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकारों को कांग्रेस ने खत्म कर दिया...और रबर स्टांप बना दिया।''

दुबे ने चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) जैसी संस्था में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता 10 साल तक अध्यक्ष रहा। उन्होंने कहा कि कई निर्वाचन आयुक्तों को राज्यपाल और मंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा, ''टी एन शेषन जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें अहमदाबाद में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया और एम एस गिल के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। मदर टेरेसा पर किताब लिखने वाले नवीन चावला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया।''

भाजपा सांसद ने परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा, ''भाजपा में अध्यक्ष को (अधिकतम) दो कार्यकाल मिलते हैं और अध्यक्ष का एक कार्यकाल तीन साल के लिए होता है। नड्डा जी 2020 में अध्यक्ष बने हैं। उनका कार्यकाल 2026 तक है।''

दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सदस्यों के लिए कहा कि आप अपने यहां देखिये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जब से पार्टी की अध्यक्ष बनी हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना और द्रमुक में करूणानिधि के परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बना है। उन्होंने कहा, ''हालांकि, शरद पवार अपवाद हो सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी में अध्यक्ष उनके परिवार के लोग नहीं हैं। लेकिन आप कांग्रेस को देख लीजिए, गांधी परिवार को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनता और यदि बनता है तो उसकी स्थिति सीताराम केसरी की तरह हो जाती है...।'' उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) 1987 में पायलट परियोजना के नाते तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी लेकर आए थे और 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो तय किया गया कि ईवीएम का उपयोग किया जाएगा।

दुबे ने कहा कि ''कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर सलमान रुश्दी तक वोट बैंक के तुष्टीकरण में फंसी हुई है और जिस कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर का विरोध किया, उसी ने अयोध्या का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज तक सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए।

अंग्रेजों से ज्यादा 'दमनकारी' है गुजरात सरकार, राजकोट जेल में किसानों से मिलने नहीं दिया गया : केजरीवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

राजकोट (गुजरात)/भाषा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें राजकोट जेल में बंद किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने गुजरात सरकार पर अंग्रेजों से भी ज्यादा ''दमनकारी'' होने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जेल में बंद किसानों से मिलने के लिए पहले से अनुमति मांगी थी।

अक्टूबर में बोटाद जिले के हद्दाद गांव में विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने 88 किसानों और आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया था। इनमें से 46 अभी भी सलाखों के पीछे हैं। केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा, ''मुझे राजकोट जेल में किसानों और किसान नेताओं से मिलने नहीं दिया गया। इससे बड़ा कोई अत्याचार हो सकता है क्या? क्या मैं आतंकवादी या अपराधी हूं? जेल में बंद लोग किसान हैं। वे हमारे देश के नागरिक हैं। वे अपराधी नहीं हैं।'' उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के साथियों को भी जेल में उनसे मिलने से नहीं रोका गया था।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि (आजादी के बाद) एक ऐसी सरकार बनेगी जो अंग्रेजों से भी बदतर, ज्यादा क्रूर और दमनकारी होगी।'' गुजरात के दौरे पर आए केजरीवाल ने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने किसानों को 24 घंटे तक पेयजल और खाना नहीं दिया। 'आप' नेता ने कहा, ''किसान परेशान हैं। उनके परिवारों ने मुझे बताया कि हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई। क्या भाजपा उनका मनोबल तोड़ना चाहती है? ईश्वर से डरो।

मल्होत्रा ने बैंक प्रमुखों से ग्राहकों को ब्याज दर कटौती का फायदा देने को कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ निजी बैंकों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और टिकाऊ वृद्धि को समर्थन करने के लिए ब्याज दर कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

फरवरी, 2025 से आरबीआई ने अब तक रेपो दर में कुल 1.25 प्रतिशत अंक की कटौती करके इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया है। भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंकों के प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक के दौरान गवर्नर ने कहा कि वर्ष 2025 में बैंकिंग क्षेत्र की सेहत और कामकाज में लगातार सुधार हुआ है लेकिन बैंकों को लापरवाही से बचना चाहिए और बदलते माहौल में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतिगत ब्याज दर में 1.25 प्रतिशत की कटौती और प्रौद्योगिकी के अधिक इस्तेमाल को जोड़ने से मध्यस्थता लागत में कमी और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे टिकाऊ वृद्धि और अधिक वित्तीय समावेशन को समर्थन मिलेगा।

मल्होत्रा ने बेहतर ग्राहक सेवा पर ज़ोर देते हुए बैंकों से शिकायतों को कम करने और आंतरिक प्रणाली को मज़बूत करने पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी से बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डाला और अधिक मज़बूत, जानकारियों से लैस सुरक्षा उपायों की मांग की।

ग्राहकों की दोबारा केवाईसी और बिना दावे वाली जमाओं पर बैंकों के प्रयासों की सराहना करते हुए आरबीआई गवर्नर ने सक्रिय पहुंच और लगातार जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नियमों के सुदृढ़ीकरण और सरलीकरण में हाल की पहलों का ज़िक्र करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के सलाहकारी दृष्टिकोण की पुष्टि की।

बैठक में डिप्टी गवर्नर टी रबि शंकर, स्वामिनाथन जे, पूनम गुप्ता और एस सी मुर्मू के साथ निगरानी, विनियमन, प्रवर्तन एवं उपभोक्ता प्रशिक्षण और वित्तीय समावेशन के प्रभारी कार्यकारी निदेशक भी मौजूद थे। यह बैठक रिजर्व बैंक की विनियमित संस्थाओं के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चल रही बातचीत का हिस्सा है। इस तरह की पिछली बैठक 27 जनवरी, 2025 को हुई थी।

संक्रांति से लोगों को सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराएं : नायडू

अमरावती/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संक्रांति त्योहार से लोगों को सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। 'रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम' (आरटीजीएस) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं से पारदर्शिता आएगी और शासन के प्रति लोगों की संतुष्टि भी बढ़ेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को अगली संक्रांति से सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी विभागों से इस दिशा में कदम उठाने को कहा है।

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख के अनुसार, सरकार की सभी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

एसआईआर पर रोक लगे, नागरिकता तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग का नहीं : मारन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रत्येक भारतीय को मतदान का अधिकार है और नागरिकता तय करने का अधिकार आयोग को नहीं है।

चुनाव सुधार के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए मारन ने कहा कि निर्वाचन आयोग को 'तटस्थ' भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने एसआईआर रोके जाने की मांग करते हुए कहा कि आयोग द्वारा राज्यों में चुनाव से तीन महीने पहले एसआईआर कराने से शंका पैदा हो रही है और इस प्रक्रिया को करने से पहले कम से कम छह महीने का समय दिया जाना चाहिए। मारन ने कहा कि निर्वाचन आयोग चाहे तो किसी राज्य के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पायलट अध्ययन करा ले। उन्होंने यह भी कहा, ''नागरिकता तय करने का काम क्या चुनाव आयोग का है। मैं भारतीय हूं और मुझे मतदान का अधिकार है। क्या आयोग को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं मतदाता हूं और बदलाव के लिए मतदान करूं, लेकिन वह लोगों पर बुरी तरह दबाव डाल रहा है।'' मारन ने यह आरोप भी लगाया कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है और इन पर आयोग रोक नहीं लगा पाता। उन्होंने मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि जर्मनी, अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में ईवीएम नहीं है तो भारत में क्यों है। मारन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''आप मतपत्र से क्यों डरते हैं। आपको विकसित देशों के मॉडल को

भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम कर रही है सरकार : जितिन प्रसाद

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ मिलकर एक लाभप्रद व्यापार समझौते के लिए गहन बातचीत समेत कई तरह की रणनीतियों के जरिये अपने निर्यात पर अमेरिकी शुल्क के असर को कम करने के लिए काम कर रही है।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि उम्मीद है कि इन उपायों से भारत के व्यापार संबंधों में मजबूती बढ़ेगी। उन्होंने कहा, ''सरकार अमेरिका के टैरिफ उपायों के भारतीय निर्यात पर असर को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है।

स्वदेशी के मंत्र से ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण होगा : उपमुख्यमंत्री साव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायपुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने राजधानी रायपुर में स्वदेशी संकल्प यात्रा को ध्वज दिखाकर रवाना किया और कहा कि स्वदेशी के मंत्र से ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण होगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और स्वदेशी जागरण मंच, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प यात्रा को उपमुख्यमंत्री साव ने आज रायपुर के तेलीबांधा तालाब परिसर में ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित मोटरसाइकिल रैली में शामिल होकर साव ने रायपुर वासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

साव ने राजधानीवासियों को संबोधित करते हुए कहा, ''भारत को खुशहाल और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से स्वदेशी का संदेश घर-घर पहुंचाने का यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। 22 दिनों तक चलने वाली यह स्वदेशी संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में सकारात्मक वातावरण तैयार कर रही है।'' उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने का यह संकल्प हमें आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाएगा तथा भारत माता के गौरव और वैभव को पुनः स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

सालाना 20 अरब डॉलर के आईपीओ भारत के लिए एक नई सामान्य बात : जेपी मॉर्गन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। सबसे बड़े निवेश बैंकरों में एक जेपी मॉर्गन ने मंगलवार को कहा कि प्रति वर्ष 20 अरब डॉलर की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) भारत के लिए नई सामान्य बात हो गई। आने वाले कुछ सालों में यह दर स्थायी होने की उम्मीद है।

बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में आईपीओ की बाढ़ के बीच बाजार में अब तक 2025 में 21/अरब डॉलर के निर्गम हो चुके हैं जो पिछले साल के बराबर है। यदि कुछ बड़े निर्गम जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का प्रस्ताव सफल होता है, तो साल के अंत तक यह राशि 23 अरब डॉलर से भी ऊपर जा सकती है।

जेपी मॉर्गन के इक्विटी पूंजी बाजार के प्रमुख अभिनव भारती ने संवाददाताओं से कहा, ''भारत के लिए सालाना 20 अरब डॉलर जारी करना नई सामान्य बात है। यह नया मापदंड है और आगे से यह हमारे लिए सालाना दर बन जाएगा।'' उन्होंने कहा कि कम से कम 20 स्टार्टअप, जिनका निजी बाजार में करोड़ों का मूल्यांकन है, वर्तमान में आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। भारती ने कहा कि मांग का लगभग पांचवां हिस्सा उपभोक्ता प्रौद्योगिकी और नए युग के व्यवसायों द्वारा संचालित हो रहा है, और अगले पांच वर्षों में यह 30 प्रतिशत से भी ऊपर चला जाएगा।

जनगणना व्यक्ति के तत्कालीन निवास पर होगी, प्रवास की अवधि और कारण पूछा जाएगा : सरकार

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि जनगणना 2027 में वर्तमान निवास पर लोगों के रहने की अवधि और प्रवास के कारण से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी उस स्थान पर एकत्र की जाती है, जहां वे गणना की अवधि के दौरान पाए जाते हैं।

मंत्री एक सदस्य के इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या जनगणना-2027 के दौरान प्रवासी श्रमिकों और अस्थायी निवासियों की गणना के लिए कोई विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं और क्या इसके लिए एक अलग डेटा संग्रह प्रक्रिया प्रस्तावित है।

केंद्र और राज्यों में टीबी रोधी दवाओं की कोई कमी नहीं : अनुप्रिया पटेल

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि आवश्यक टीबी-रोधी दवाओं रिफैम्पिसिन और एथैम्बूटॉल की केंद्र और राज्य स्तरीय भंडारों में कोई कमी नहीं है।

पटेल ने हाल के महीनों में तपेदिक रोधी प्रमुख दवाओं की कमी, केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों से जुड़े प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनटीईपी देशभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा, केंद्रीय और राज्य गोदामों में रिफैम्पिसिन और एथैम्बूटॉल सहित किसी भी प्रमुख तपेदिक रोधी दवा की कोई कमी नहीं है। वर्ष 2025-27 के लिए सभी दवाओं, जिनमें नई और कम अवधि की उपचार योजनाओं की दवाएं शामिल हैं, के लिए दर अनुबंध मॉडल स्थापित किया गया है और पर्याप्त बफर स्टॉक भी सुनिश्चित किया गया है।

उनके अनुसार, गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें समय पर खरीद एजेंसी को ब्यौरा भेजना, डीवीडीएमएस (दवाएं एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से उपलब्धता और उपयोग की 'रियल-टाइम' निगरानी, राज्य, जिले और राष्ट्रीय टीमों द्वारा क्षेत्रीय दौरों के दौरान नियमित स्टॉक सत्यापन तथा राज्य एवं जिला स्तर पर सतत निगरानी शामिल हैं।

सरकार 'वंदे मातरम्' नारे के पीछे अपने गुनाहों को छिपा रही है : सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संजय सिंह ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि 'वंदे मातरम्' नारे के पीछे वह अपने गुनाहों को छिपा रही है।

'वंदे मातरम्' की रचना के 150 साल पूरा होने पर राज्यसभा में हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए आप सदस्य सिंह ने कहा कि 'वंदे मातरम्' नारा देशभक्ति के लिए है लेकिन यह सरकार ऐसे नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभक्ति की बात करने वाली सरकार हवाई अड्डा, रेल, सरकारी कंपनियों को बेच रही है।

उन्होंने दावा किया कि शहीद खुदीराम बोस, शहीद-ए-आजम भगत सिंह सहित तमाम शहीदों और क्रांतिकारियों ने 'वंदे मातरम्' के नारा लगाए लेकिन भाजपा के पूर्ववर्ती संगठनों ने उस समय आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। सिंह ने सवाल किया, ''...उस समय आपके पुरखे क्या कर रहे थे। आरएसएस अपने चार लोगों के नाम बता दे...आजादी की लड़ाई में आपकी कोई भूमिका नहीं है, यही आपकी कुंठा है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) ने लंबे समय तक राष्ट्रीय ध्वज का विरोध किया और अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के मुखपत्र आर्गनाइजर में राष्ट्रगान का विरोध तक किया गया।

वर्तमान में केवल 3 जिले वामपंथी उग्रवाद से 'सबसे अधिक प्रभावित' हैं : नित्यानंद राय

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सुरक्षा बलों ने 2019 से अब तक 29 शीर्ष नक्सलियों को मार गिराया और अकेले इस साल माओवादियों की केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो के 14 सदस्य मारे गए हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या 2014 के 10 से घटकर 2025 (अक्टूबर तक) पांच रह गई है, जो 50 प्रतिशत की कमी है। उन्होंने कहा कि वहीं, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या में भी इस अवधि के दौरान 91 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई और यह संख्या 126 से घटकर 11 रह गई। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 के 126 से घटकर अक्टूबर 2025 में मात्र 11 रह गई। मंत्री ने कहा कि अब केवल तीन जिले ही वामपंथी उग्रवाद से ''सबसे अधिक प्रभावित'' हैं। मंत्री ने दावा किया कि वामपंथी उग्रवाद ''मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा।'' नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार की 'कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति' के परिणाम को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा में 2010 के उच्चतम स्तर से 2024 तक 81 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

भारत में सी-130जे विमानों के लिए सह-उत्पादन प्रतिष्ठान स्थापित करने की योजना : लॉकहीड मार्टिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अमेरिकी वैमानिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में 'सी-130जे सुपर हरक्यूलिस हेवी-लिफ्ट' सैन्य परिवहन विमान के सह-उत्पादन के लिए एक प्रतिष्ठान स्थापित करने की योजना बना रही है, जो अमेरिका के बाहर पहला ऐसा वैश्विक केंद्र होगा।

भारतीय वायुसेना द्वारा 80 सामरिक परिवहन विमानों की खरीद की शुरुआत के साथ, लॉकहीड मार्टिन ने सी-130जे विमान को बल के लिए सर्वोत्तम विकल्प बताया है, जिसे भारत और 20 से अधिक अन्य देशों में एक विश्वसनीय विमान माना गया है। लॉकहीड मार्टिन एयरोनॉटिक्स के उपाध्यक्ष (व्यावसायिक विकास, वायु गतिशीलता और समुद्री मिशन) रॉबर्ट टोथ ने कहा कि भारतीय वायुसेना का मध्यम परिवहन विमान (एमटीए) कार्यक्रम कंपनी को न केवल भारत में क्षमता लाने का अवसर देता है, बल्कि इसके औद्योगिक आधार को भी आगे बढ़ाने का अवसर देता है। उन्होंने पीटीआई-भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा, ''हम एमटीए से पहले सी-130जे में निवेश जारी रखे हुए हैं और भारत में विमान बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।''

टोथ ने कहा, ''वास्तव में, दुनिया भर में उपलब्ध सभी अवसरों में से भारत पहला देश है, जहां हमने वचन दिया है कि हम अमेरिका के बाहर भारत में सह-उत्पादन प्रतिष्ठान स्थापित करेंगे।'' भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 12 सी-130जे सुपर हरक्यूलिस विमान हैं।

लॉकहीड मार्टिन की सह-उत्पादन प्रतिष्ठान स्थापित करने की योजना काफी हद तक एमटीए सौदे के लिए ठेका प्राप्त करने में सफलता से जुड़ी है।

अमेरिकी रक्षा कंपनी ने सी-130जे सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए बोली लगाने के वास्ते टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है।

भारतीय वायुसेना ने सोवियत युग के एएन-32 और आईएल-76 विमानों के अपने पुराने बेड़े को बदलने के लिए 2022 में मध्यम परिवहन विमान (एमटीए) खरीदने के वास्ते सूचना के लिए अनुरोध (आरएफआई) जारी किया था।

भारतीय वायुसेना लगभग 80 सैन्य परिवहन विमान खरीदने की योजना बना रही है, और अरबों डॉलर की इस खरीद को अगले कुछ हफ्तों में रक्षा खरीद परिषद से मंजूरी मिलने की संभावना है।

'वंदे मातरम्' किसी एक धर्म का या मजहब का नहीं : प्रफुल्ल पटेल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सदस्य के प्रफुल्ल पटेल ने 'वंदे मातरम्' को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि यह किसी एक धर्म का या मजहब का नहीं है बल्कि यह समूचे भारत को आजादी की सांस देने वाला जीवनदायक मंत्र है। 'वंदे मातरम्' की रचना के 150 साल पूरे होने पर उच्च सदन में हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए पटेल ने कहा ''जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक हिंदुस्तान रहेगा और जब तक हिंदुस्तान रहेगा, तब तक वंदे मातरम् रहेगा।''

उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम्' ने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब यह 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना है क्योंकि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकजुट हो कर समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना होगा तब ही हम 2047 तक विकसित भारत बना पाएंगे। चर्चा में हिस्सा ले रहे बीआरएस सदस्य के आर सुरेश रेड्डी ने कहा कि विविधता में एकता भारत की खूबसूरती है और हमारा मूल मंत्र 'वंदे मातरम्' है। उन्होंने कहा कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब 'वंदे मातरम्' ने बच्चे-बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना भर दी थी। उन्होंने कहा ''अंग्रेजों को वंदे मातरम् की शक्ति का अहसास हो गया। उनका दमन तेज हुआ किसी न किसी रूप में और वंदे मातरम् ने देशभक्ति की भावना को लगातार मजबूती दी। नतीजा भारत की आजादी के रूप में सामने आया।'' माकपा के वी शिवदासन ने कहा ''वंदे मातरम् पर चर्चा करते समय हमें इसकी एक-एक पंक्ति को याद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारे देश में क्या हर मां अपने बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के साथ इस देश की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार कर पा रही है? क्या हम वंदे मातरम् के रचयिता का और इसका उद्घोष करने वालों का सपना पूरा कर पाए हैं? '' जद (यू) के संजय कुमार झा ने कहा कि आपस की कलह छोड़ कर विकास की ओर ध्यान देना होगा, तब ही 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का सपना सच हो पाएगा।

केंद्र किसानों की समस्याएं हल करने के लिए कर्नाटक के साथ सहयोग नहीं कर रहा : शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए इस दक्षिणी राज्य के साथ सहयोग नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि विधानमंडल का चालू शीतकालीन सत्र राज्य के ज्वलंत मुद्दों मुख्य रूप से किसानों पर केंद्रित होगा। उन्होंने विपक्ष से फसल खरीद और क्षेत्रीय विकास के मुद्दे को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए सरकार के साथ आने का आग्रह किया।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ''हमें नहीं पता कि केंद्र इस मामले को सुलझाने में हमारे साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहा। हमें नहीं पता कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत फसलों की खरीद के लिए धनराशि क्यों जारी नहीं कर रहा।''

कर्नाटक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेलगावी में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने किसानों के साथ हो रहे ''अन्याय'' के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। शिवकुमार ने भाजपा के प्रदर्शन के आह्वान की आलोचना की और सिंचाई एवं फसल खरीद पर निर्णायक कदम उठाने के पार्टी के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, ''क्या भाजपा ने कभी अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (यूकेपी), गन्ना और मक्का खरीद पर हमारे जैसे ठोस फैसले लिए हैं?'' फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में केंद्र की जिम्मेदारी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ''एमएसपी कौन तय करता है? केंद्र ही तय करता है। पिछले 10 वर्ष से उसने चीनी की कीमतें नहीं बढ़ाईं। वे मिलों को समर्थन देने का फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं?''

उन्होंने कहा कि किसानों को बचाया जाना चाहिए, भले ही इससे नुकसान ही क्यों न हो। शिवकुमार ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन को खारिज करते हुए कहा, ''चूंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं।'' इस बीच, यतींद्र सिद्दरामय्या के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उनके पिता सिद्दरामय्या मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, शिवकुमार ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है।''

यतींद्र ने सोमवार को दावा किया था कि कांग्रेस आलाकमान ने कहा है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और उनका मानना है कि सिद्दरामय्या मुख्यमंत्री के रूप में पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

यतींद्र ने नेतृत्व पर जो कहा, वह समझ में नहीं आया : शिवकुमार

बेलगावी। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि उनके और मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के बीच कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा की गई टिप्पणी उन्हें समझ में नहीं आयी। सिद्दरामय्या के बेटे एवं विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) यतींद्र सिद्दरामय्या ने कहा था कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं है'' और उनका मानना है कि सिद्दरामय्या पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस टिप्पणी ने संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को फिर से हवा दे दी है। यह टिप्पणी सिद्दरामय्या और शिवकुमार के बीच नाश्ते पर मुलाकात के एक दौर के बाद आयी है।

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ''सब कुछ ठीक है। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई मतभेद नहीं है। यह कभी नहीं था, यह आज नहीं है और यह भविष्य में भी नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने (यतींद्र) क्या कहा है। मैं उनसे बात करूंगा।'' उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई अपनी बातचीत का ब्योरा देने या इस बारे में बताने से इनकार कर दिया कि अगली बार बैठक के लिए कब बुलाया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने उनके समर्थन में बोलने वालों को नोटिस क्यों जारी किया, लेकिन यतींद्र को नहीं, तो शिवकुमार ने बस इतना कहा, ''मैं उनसे बात करूंगा...।'' यतींद्र की टिप्पणी के बाद, सिद्दरामय्या ने सोमवार को दोहराया कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगा, वह उसका पालन करेंगे।

बेलगावी में विरोध मार्च के दौरान भाजपा नेताओं, किसानों को हिरासत में लिया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। कांग्रेस सरकार की 'कथित किसान विरोधी नीतियों' के खिलाफ सुवर्ण विधान सौधा की ओर मार्च कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा सहित कई प्रदर्शनकारियों को मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। विजयेंद्र, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी के अलावा कई विधायकों, विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ मालिनी सिटी ग्राउंड में एकत्र हुई।

कर्नाटक विधानसभा का 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र यहां सुवर्ण विधान सौध में जारी है, जो आठ दिसंबर को शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच, भाजपा नेता और किसान ग्राउंड से सौधा की ओर कूच करने लगे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और पुलिस वैन में ले जाया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए कांग्रेस सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों और ''कांग्रेस सरकार की विफलताओं'' को उजागर करने के मकसद से किया गया। इससे पहले, विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष के कारण 'नीतिगत पंगुता' हो गयी है, जिससे सिद्दरामय्या के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने में असमर्थ हो गई है।

उन्होंने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, ''कर्नाटक में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। अंदरूनी कलह और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिये होड़ के कारण प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। इसलिए आज हमने इस सरकार के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांग है कि सिद्दरामय्या सरकार किसानों से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान करे।''

उन्होंने कहा, ''एफआरपी (उचित एवं लाभकारी मूल्य) तय करना केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य को एफआरपी से अधिक कीमत घोषित करने से कुछ भी नहीं रोकता। देश का तीसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कर्नाटक हर साल 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित करता है। लेकिन जब किसान विरोध कर रहे थे, तो सरकार ने केवल 50 रुपये प्रति टन देने का फैसला किया।'' उन्होंने आरोप लगाया कि मक्का उत्पादकों की मांगें भी पूरी नहीं की गई हैं।

भाजपा ने राज्य सरकार पर मक्का एवं गन्ना किसानों की चिंताओं का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया और दावा किया कि मक्का किसान खरीद केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसे राज्य सरकार ने अब तक नहीं खोला है।

मैं विपक्ष का असली नेता हूं, मुझे उपाध्यक्ष के बगल वाली सीट आवंटित की जाए : विधानसभा में बोले यतनाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। भाजपा से निष्कासित वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा में कहा कि वह विपक्ष के ''असली नेता'' हैं और विधानसभा अध्यक्ष को उन्हें उपाध्यक्ष के बगल वाली सीट आवंटित करनी चाहिए। यतनाल ने अध्यक्ष से अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें और दो अन्य विधायकों (जो भाजपा से निष्कासित होने के बाद अब असंबद्ध सदस्य हैं) को उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अग्रिम पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था की जाए। भाजपा ने यतनाल, एस टी सोमशेखर और ए शिवराम हेब्बार को इस वर्ष के शुरू में निष्कासित कर दिया था तथा इसके बाद सदन में उनके बैठने की व्यवस्था पिछली सीटों पर की गई थी। यतनाल ने कहा, ''वरिष्ठ विधायकों को पीछे की सीट पर बैठाकर उनका अपमान किया गया है। पिछले सत्र में भी ऐसा किया गया था। हम पांच से छह बार चुने गए हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें आगे की पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।'' उन्होंने अध्यक्ष से उनके बैठने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि कल तक इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए।

इस पर हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष यू टी खादर ने यतनाल से कहा कि राजनीति में कोई वरिष्ठ या कनिष्ठ नहीं होता। उन्होंने कहा, ''जो सत्ता में है, वह वरिष्ठ है और जो सत्ता से बाहर है, वह कनिष्ठ है।'' उन्होंने कहा कि सीट वरिष्ठता के आधार पर आवंटित नहीं की जातीं, जिनके पास बहुमत है उन्हें सदन में सत्ता पक्ष की सीट मिलेगी और जिनके पास संख्या बल कम है, उन्हें विपक्ष की सीट मिलेगी। यह उल्लेख करते हुए कि भाजपा में रहने के दौरान यतनाल को आगे की सीट दी गई थी, अध्यक्ष ने पूछा कि अगर वह पार्टी से बाहर हो गए हैं, तो क्या किया जा सकता है?

उन्होंने कहा, यदि आप (यतनाल) सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्षी पार्टी का हिस्सा हैं, तो आपको संबंधित पक्षों में आगे की सीट मिलेगी।'' इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यतनाल ने दावा किया कि वह विधानसभा में विपक्ष के ''असली नेता'' हैं।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष आर अशोक सदन में मौजूद थे। यतनाल ने कहा, ''मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, जो किसी तरह का समायोजन करता हो। मैंने किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। मैं मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गया हूं, किसी मंत्री से कोई अनुरोध नहीं किया है। इसलिए मैं विपक्ष का असली नेता हूं और आप मुझे उपाध्यक्ष के बगल वाली सीट आवंटित कर सकते हैं (जो विधानसभा में विपक्ष के नेता के लिए आवंटित सीट है)।'' यतनाल भाजपा में रहते हुए और पार्टी से निकाले जाने के बाद भी राज्य में भाजपा नेतृत्व पर सत्तारूढ़ कांग्रेस नेताओं के साथ ''समायोजन की राजनीति'' में लिप्त होने का आरोप लगाते रहे हैं।

वन मंत्री ने की 532 एकड़ वन भूमि हड़पने की साजिश की सीआईडी जांच की मांग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या को पत्र लिखकर 532 एकड़ वन और सरकारी भूमि हड़पने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़ी साजिश की सीआईडी जांच और एक अनुकूल अदालती आदेश हासिल करने की मांग की है। खांड्रे के अनुसार एम बी नेमन्ना गौड़ा उर्फ एम बी मन्मथ नामक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने निर्देश दिया कि 532 एकड़ भूमि, जिसमें बेंगलूरु के केंगेरी में बीएम कवल के पास 482 एकड़ आरक्षित वन भूमि भी शामिल है, के अभिलेख तीन महीने के भीतर उसके नाम पर स्थानांतरित कर दिए जाएं।

अपने पत्र में मंत्री ने कहा कि सरकार को इस घटनाक्रम की जानकारी अंतिम समय में मिली। उन्होंने कहा कि ''90 दिन की समय सीमा समाप्त होने से एक दिन पहले तक सरकार के अतिरिक्त सरकारी वकील योगन्ना ने यह जानकारी न तो सरकार को दी और न ही वन विभाग को।''

वन मंत्री ने कहा कि अगर विभाग को आखिरी समय में सूचित नहीं किया जाता, तो हम लगभग 25,000 करोड़ रुपये की यह ज़मीन खो देते। वन मंत्री ने कहा कि उन्होंने एक तत्काल बैठक बुलाई और अधिकारियों को अपील दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मन्मथ उर्फ़ नेमन्ना गौड़ा ने पहले भी ''नकली दस्तावेज़'' पेश करके सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी।

मंत्री ने कहा कि चिक्कमगलूरु के तत्कालीन उप-मंडल अधिकारी देबजीत कुमार ने 25 सितंबर 2024 के एक आदेश में निर्देश दिया था कि मन्मथ के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। खांड्रे ने कहा कि बीएम कवल का मामला सामने आने के बाद उन्होंने अधिकारियों को चिकमंगलूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। खांड्रे ने एक बयान में कहा, ''हालांकि मूडीगेरे क्षेत्राधिकारी को 28 नवंबर 2025 को शिकायत मिली थी, लेकिन अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।'' उन्होंने इस देरी को संदिग्ध बताया।

खांड्रे ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अधिकारियों और अतिरिक्त सरकारी वकील ने हज़ारों करोड़ रुपये की ज़मीन हड़पने की कोशिश करने वालों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे एक विशेष जांच दल गठित करें या मामले की व्यापक जांच के लिए इसे सीआईडी को सौंप दें तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बेलगावी में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने मंगलवार को बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर सिद्दरामय्या ने कहा कि भारतीय तिरंगा केवल खादी का कपड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्र के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। राज्य सरकार ने कहा कि यह ''दूसरा सबसे बड़ा'' खादी राष्ट्रीय ध्वज है। बताया गया कि ऐसा सबसे बड़ा तिरंगा 2021 में लेह में फहराया गया था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिद्दरामय्या ने याद दिलाया कि तिरंगे को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। सिद्दरामय्या ने कहा, यह केवल खादी का कपड़ा नहीं, बल्कि भारत के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। ध्वज में तीन रंग और अशोक चक्र है। केसरिया, सफेद और हरा रंग राष्ट्रीय गौरव, अर्थव्यवस्था, बलिदान और शांति का संदेश देते हैं, साथ ही भारतीयों को देशभक्ति की प्रेरणा भी देते हैं। उन्होंने कहा, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और इसे गर्व से देखना चाहिए। सभी को देशभक्ति का भाव रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर और कलबुर्गी जिले के कमलापुर निवासी विनोद कुमार रेवप्पा बामन्ना के परिवार के सदस्यों को बधाई दी, जिन्होंने यह ध्वज दान किया।

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि यह तिरंगा झंडा लोगों में राष्ट्रीय भक्ति का संचार करेगा। इससे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सदन के अध्यक्ष यूटी खादर, रुद्रप्पा लमानी और उनकी टीम को बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि इसे जनता के दर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लमानी, मंत्री डॉ. एचसी महादेवप्पा, लक्ष्मी हेब्बाल्करा, सलीम अहमद, अशोक पट्टाना, नासिर अहमद, रेवन्ना, थम्मैया, सरकार के मुख्य सचिव शालिनी रजनीश और अन्य उपस्थित थे।

टीवीके की रैली में बंदूक लेकर घुसा व्यक्ति गिरफ्तार

पुडुचेरी। तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने मंगलवार को यहां अभिनेता विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली में बंदूक लेकर घुसने की कोशिश की, जिससे हड़कंप मच गया। सतर्क पुलिसकर्मियों ने हालांकि उसे हिरासत में ले लिया और उप्पलम के एक्सपो ग्राउंड (न्यू पोर्ट) में आयोजित रैली में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की कड़ी तलाशी ली। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उस व्यक्ति ने खुद को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले का निवासी बताया और कहा कि वह एक निजी सुरक्षा अधिकारी है, जो समय पर अपनी टीम में शामिल नहीं हो सका। हिरासत में लिये गये व्यक्ति ने दावा किया कि उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है।

जब पत्रकारों ने उसकी पहचान पूछी और पूछा कि वह किसे सुरक्षा दे रहा था, तो उस व्यक्ति ने जवाब देने से इनकार कर दिया और बताया कि उसके पास बंदूक का लाइसेंस है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने पिस्तौल अपनी कमर के बाईं ओर रखी हुई थी और कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब उसकी तलाशी ली तब उन्हें बंदूक का पता चला। टीवीके की रैली में केवल 5,000 लोगों को प्रवेश दिये जाने की मंजूरी दी गयी थी। पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों और गहन तलाशी के बावजूद टीवीके समर्थक और विजय के प्रशंसक बड़ी संख्या में आयोजन स्थल पर पहुंचे और उनमें से कुछ अभिनेता की एक झलक पाने के लिए पास के पेड़ों पर चढ़ गए। करूर में 27 सितंबर को विजय की रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गयी थी।

कांग्रेस विधायक की मांग के बाद कर्नाटक में फिर भड़का टीपू जयंती विवाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेलगावी। कर्नाटक में टीपू की जयंती को लेकर विवाद फिर भड़क गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक शिवानंद कशप्पनवार ने 18वीं सदी के मैसूरु शासक की जयंती के आयोजन को लेकर कर्नाटक विधानसभा में ध्यानार्षण प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, सिद्दरामय्या ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। हालांकि इस मुद्दे पर कोडागु समेत विभिन्न स्थानों पर हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस परंपरा पर विराम लगा दिया गया था। कोडागु में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में पुलिस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। प्रदर्शनों के बाद टीपू की जयंती बेहद सादगी से मनाई गई और बाद में धीरे-धीरे इसे स्थगित कर दिया गया। अब हुंगुंड विधायक ने एक बार फिर इसे तूल दिया है। कशप्पनवर चाहते हैं कि सरकार टीपू की जयंती को प्रायोजित करे, जिस पर विपक्षी भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा ने कहा है कि वह इसका कड़ा विरोध करेगी। कशप्पनवर ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने टीपू की जयंती के आयोजन को लेकर प्रस्ताव दिया है। हमें राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कद्दावर नेता बीएस येडीयुरप्पा ने खुद टीपू की तरह पोशाक धारण की और जयंती समारोह में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक ने कहा, जब उन्हें जरूरत थी तब उन्होंने इसे मनाया, लेकिन अब वे नहीं चाहते कि टीपू जयंती को मनाया जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका आयोजन हो। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने पत्रकारों से कहा, ''वे चाहे टीपू जयंती मनाए, ओसामा बिन लादेन का जन्मदिन और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाए। यह उनकी सरकार है। जनता को पता चल जाएगा कि उनका झुकाव किसकी तरफ है।''

कर्नाटक के वक्फ और आवास मंत्री बी जेड जमीर अहमद खान ने संवाददाताओं से कहा कि वह टीपू जयंती का आयोजन करते रहे हैं। देश भर में टीपू अनुयायी टीपू जयंती का आयोजन करते आ रहे हैं। हमने भी पिछले महीने इसका आयोजन किया था। सिद्दरामय्या इसे विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया करते थे, जिसे अब रोक दिया गया है। जब वहां इसका आयोजन बंद कर दिया गया है, क्या हमें इसे कहीं और आयोजित नहीं करना चाहिए।

टीवीके नेता सेनगोट्टैयन के भतीजे अन्ना द्रमुक में शामिल हुए

चेन्नई। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) नेता के.ए. सेनगोट्टैयन के भतीजे के के सेल्वम मंगलवार को अन्नाद्रमुक महासचिव ई. के. पलानीस्वामी की उपस्थिति में उनकी पार्टी में शामिल हो गए। सेल्वम पहले इरोड उत्तर जिले में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की पर्यावरण शाखा से जुड़े थे। वह अपने समर्थकों के साथ अन्नाद्रमुक (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम) में शामिल हो गए। उनके पिता के. ए. कलियाप्पन टीवीके नेता सेनगोट्टैयन के बड़े भाई हैं। आधी सदी तक अन्नाद्रमुक में काम करने के बाद सेनगोट्टैयन अभिनेता से नेता बने विजय की अगुवाई वाली टीवीके में हाल में शामिल हो गए थे और उन्हें पार्टी का मुख्य संयोजक बनाया गया।

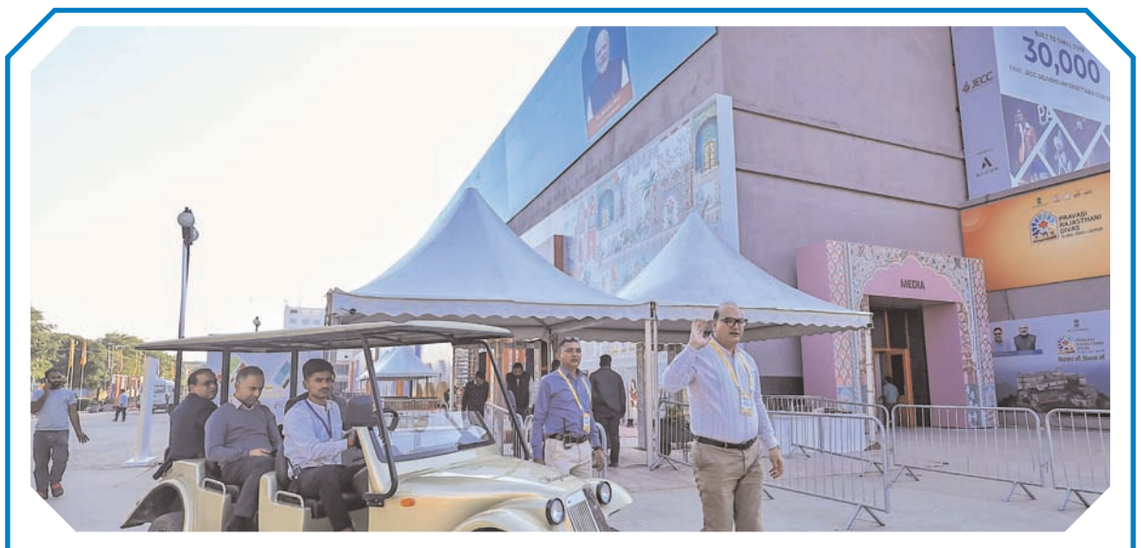

पहला 'प्रवासी राजस्थानी दिवस', कई दिग्गज होंगे शामिल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार को होने वाले पहले 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' में देश और दुनिया से प्रवासी समुदाय भाग लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस समारोह का उद्देश्य देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे प्रवासी राजस्थानियों के राज्य से संबंधों को मजबूत करना और राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में पहुंचाने में प्रवासियों के योगदान का उत्सव मनाना है। जेईसीसी सभागार में उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा। वह प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ आपसी संबंधों को बढ़ाने, राज्य के आर्थिक विकास, वैश्विक साझेदारी और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए अपनी सरकार के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। उद्घाटन सत्र में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी संबोधित करेंगे। आयोजन की शुरुआत राजस्थान की विकास यात्रा और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की झलक दिखाने वाली प्रदर्शनी 'प्रगति पथ' के उद्घाटन के साथ होगी।

इसके बाद राज्य के उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आगंतुकों का स्वागत करेंगे। उद्घाटन सत्र में देश के कारोबार और उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां भी शामिल होंगी, जिनमें वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल और टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीर सिन्हा शामिल हैं। साथ ही, देश-विदेश में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानी समुदाय की कुछ विशिष्ट हस्तियों को 'प्रवासी राजस्थानी सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस का एक और खास आकर्षण प्रवासी राजस्थानियों के साथ खुली चर्चा है, जिसमें राजस्थान के विकास हेतु प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग बढ़ाने और निवेश के अवसरों पर संवाद होगा। इसके अलावा, विषय आधारित सात क्षेत्रवार सत्रों का भी आयोजन किया गया है।

मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 'वंदे मातरम' का सहारा ले रहा है भाजपा : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 'वंदे मातरम' का सहारा ले रहे हैं। गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा कि जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि स्वस्थ इंसान बीमार पड़ रहा है, बच्चे और बुजुर्ग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब संसद की प्राथमिकता 'साफ हवा' पर चर्चा होनी चाहिए थी।

उन्होंने लिखा, लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी विफलताओं से घिरा भाजपा-आरएसएस नेतृत्व मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 'वंदे मातरम' का सहारा ले रहा है।'

जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के मामले में छह अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं के मामले में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सहित छह अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी दी है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करते हुए भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन कर्मचारियों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन की निविदा में फर्जीवाड़ा और मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने के आरोपों के संबंध में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव और विभाग के पांच अधिकारियों के खिलाफ धारा 17-ए में विस्तृत जांच और अनुसंधान कार्यवाही का पूर्वानुमोदन किया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही कार्रवाई की निरंतरता में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17-ए में विस्तृत जांच का अनुमोदन किया गया है। इसमें कहा कि निविदा कार्य से जुड़े तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों में गड़बड़ी के जिम्मेदार मुख्य अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता सहित तकनीकी सदस्यों तथा सचिव स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का अनुमोदन किया गया है, ताकि सभी पक्ष उजागर हो सकें और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

बयान के अनुसार, इसके अलावा राजकीय दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी करने के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी के खिलाफ अखिल भारतीय सेवाएं (वर्गीकरण, अनुशासन एवं अपील) 1969 के नियम आठ के तहत नयी जांच कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया है। इसमें कहा कि साथ ही, राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के नियम 34 के तहत पांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दंड को यथावत रखने का अनुमोदन किया गया है।

विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए विधायक निधि से पैसा दें एमएलए : दिलावर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदयपुर। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सभी विधायकों (एमएलए) से अनुरोध किया है कि वे अपने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की 20 प्रतिशत राशि सरकारी विद्यालय के भवनों की मरम्मत के लिए दें। उन्होंने इस संबंध में विधायकों को पत्र लिखा है। दिलावर ने राज्य के सभी विधायकों को पत्र लिखकर अपने विधायक निधि की 20 फीसदी राशि विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

एक प्रवक्ता के अनुसार शिक्षा मंत्री दिलावर ने विधायकों को अपनी तरफ से जारी पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के राजकीय विद्यालय के भवनों का तकनीकी दलों द्वारा सर्वे कराया गया।

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 3768 विद्यालयों के सम्पूर्ण भवन, 83783 कक्ष, 16765 शौचालय जर्जर अवस्था में हैं तथा 219902 कक्षों एवं 29753 शौचालयों में मरम्मत की जरूरत बताई गई।

पत्र के अनुसार इस वर्ष मानसून में भारी वर्षा को देखते हुए राजकीय विद्यालयों के भवनों में मरम्मत/जर्जर कक्षों के स्थान पर नवीन कक्षों के निर्माण/जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है। इतने बड़े निर्माण कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अत्यधिक राशि चाहिए। मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के राजकीय विद्यालय के भवनों के लिए विधायक निधि से 20 प्रतिशत राशि वार्षिक 'विधायक शिक्षा का साथी योजना' के अन्तर्गत व्यय किये जाने की घोषणा की गयी है।

मंत्री ने कहा कि वह विधायकों से आग्रह करते हैं कि वे राजकीय विद्यालयों के जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए अपने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि की 20 प्रतिशत राशि (एक करोड़ रुपये) खर्च करें।

गहलोत समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सोनिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा अन्य पार्टी नेताओं ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। सोनिया गांधी मंगलवार को 79 वर्ष की हो गईं। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा,भारतीय राजनीति में त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति, देश में अधिकार आधारित युग की सूत्रधार और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा,देश की विविधता, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए आपका दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने सोनिया गांधी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा,आपके दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रहित के प्रति अटूट समर्पण ने कांग्रेस पार्टी को हमेशा राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा दी है। आपने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जनहित के लिए समर्पित आपका योगदान ही हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

अदालत ने फिल्मकार विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

उदयपुर। यहां की एक अदालत ने 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार फिल्मकार विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को मंगलवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इस दंपति को सात दिसंबर को मुंबई से गिरफ्तार किया था और वह इन्हें सोमवार देर रात उदयपुर लाई। दोनों को मंगलवार दोपहर यहां की एक अदालत में पेश किया गया। लोक अभियोजक ने कहा कि पुलिस ने अदालत में दलील दी कि भट्ट के मुंबई कार्यालय से बिल, दूसरे दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद करने हैं। इसके आधार पर अदालत ने भट्ट और उनकी पत्नी को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्हें 16 दिसंबर को फिर अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस उपाधीक्षक छगन राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम मुंबई गई और सात दिसंबर को भट्ट व उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 'ट्रांजिट रिमांड' पर उदयपुर लाया गया। उल्लेखनीय है कि यह गिरफ्तारी डॉ. अजय मुर्डिया द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी के आधार पर की गई है। मुर्डिया ने भट्ट दंपति और छह अन्य लोगों पर उनकी दिवंगत पत्नी पर बायोपिक समेत कई फिल्में बनाने के बहाने 30 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी करने का आरोप लगाया था।

उन्होंने प्राथमिकी में कहा कि वह एक संगीत समूह के माध्यम से दिनेश कटारिया के संपर्क में आए, जिसने दावा किया कि उसके मुंबई फिल्म उद्योग में अच्छे संबंध हैं। वह अप्रैल 2024 में मुंबई के एक स्टूडियो गए, जहां कटारिया ने उनका परिचय भट्ट से कराया। उन्होंने कहा, निर्देशक ने कथित तौर पर उन्हें आश्वासन दिया कि वह पूरी फिल्म निर्माण प्रक्रिया संभालेंगे और उन्हें धन भेजते रहने के लिए कहा। डॉ. मुर्डिया ने आरोप लगाया कि यह धोखाधड़ी 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा की है। पुलिस ने कहा कि यह धोखाधड़ी आरोपियों द्वारा बनाए गए नकली बिल के जरिए की गई।

कोटा-बूंदी-झालावाड़-बारां के लाखों लोगों तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल

जयपुर/दक्षिण भारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य के प्रत्येक परिवार को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना एवं परवन-अकावद पेयजल परियोजना के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कोटा-बूंदी-झालावाड़-बारां जिले के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर कुल 5 हजार 184 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना के माध्यम से कोटा एवं बूंदी जिले के 749 गांव एवं 6 कस्बों के 1 लाख 13 हजार 287 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध होगा। सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 1 हजार 661.14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा एवं बूंदी के लिए 1 इन्टैक पंप गृह निर्माण, 3 जल शोधन संयंत्र निर्माण, 14 स्वच्छ जलाशय तथा 137 उच्च जलाशय का निर्माण होगा। इसके माध्यम से कोटा एवं बूंदी जिले के लिए 58.45 किलोमीटर लम्बी रॉ वॉटर राइजिंग मेन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। नौनेरा वृहद परियोजना से 4 हजार 506.89 किलोमीटर लम्बी राइजिंग मेन, कलस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइप लाइन का निर्माण होगा। साथ ही, कोटा एवं बूंदी में कुल 14 पंप गृह निर्माण किए जाएंगे। इसी प्रकार, परवन-अकावद पेयजल परियोजना से झालावाड़-बारां-कोटा जिले के लाखों परिवार लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से बारां के 907, कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र 184 तथा झालावाड़ के 311 गांव सहित कुल 1 हजार 402 गांव व 276 ढाणियों को लाभ होगा तथा इन जिलों के लगभग 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। इस परियोजना के लिए 3 हजार 523.16 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। परियोजना के अन्तर्गत कोटा एवं झालावाड़ के लिए 2 इन्टैक पंप गृह निर्माण, 2 जल शोधन संयंत्र निर्माण, 41 स्वच्छ जलाशय तथा 276 उच्च जलाशय का निर्माण होगा। इसके माध्यम से बारां-कोटा-झालावाड़ जिले के लिए कुल 661 किलोमीटर लम्बी मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। परवन अकावद पेयजल परियोजना से 9 हजार 477 किलोमीटर लम्बी राइजिंग मेन, कलस्टर वितरण एवं ग्रामीण वितरण पाइप लाइन का निर्माण होगा। इन दोनों परियोजनाओं को अगस्त 2027 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जल जीवन मिशन प्रदेश में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए एक अति महत्वकांक्षी परियोजना है। जेजेएम के अन्तर्गत इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से राज्य सरकार के आमजन तक स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के संकल्प को गति मिलेगी।

किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद एवं बीज समय उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध : डॉ. किरोडी लाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य के कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज एवं पेस्टिसाइड समय पर मिले एवं इनकी कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि राज्य में पिछले वर्ष 2024-25 में रबी की बुवाई 95 लाख 85 हजार हैक्टेयर में की गई थी। रबी 2025-26 में 105 लाख 60 हजार हैक्टेयर में बुवाई की जा चुकी है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रबी फसल का रकबा बढ़ा है। कृषकों को रबी 2025-26 में उच्च गुणत्ता के कृषि आदान उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में रबी गुण नियंत्रण अभियान 23 सितम्बर से 15 नवम्बर तक चलाया गया। इस अभियान के तहत कृषि आदानों के कुल 304 निर्माताओं व विक्रेता परिसरों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुल 4 हजार 87 नमूने लेकर विश्लेषण हेतु विभिन्न प्रयोगशालाओं में भिजवाये गये हैं।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम की धाराओं का उल्लघंन करने पर 56 निर्माता, विक्रेता परिसर के लाइसेंस निलंबित तथा 8 फर्मों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने कहा कि राज्य में यूरिया डाइवर्जन को रोकने हेतु 24 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ताकि पात्र किसानों को समय पर यूरिया मिल सके। उक्त अभियान के तहत यूरिया डाइवर्जन के 420 कट्टे जब्त करने की कार्रवाई की गई है। कृषि आयुक्तालय स्तर से भी टीमों का गठन किया गया है जो कि जिलों में औचक निरीक्षण करने की कार्यवाही कर रहे हैं। सभी जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों को सघन निरीक्षण कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध करवाने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है एवं इस प्रकार की ठोस कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी।

कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया

जयपुर। राजस्थान में सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन दिन का तापमान कई स्थानों पर सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के जयपुर केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। इसने कहा कि फिलहाल शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो सामान्य है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान आठ से 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। आईएमडी ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। इसने कहा कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट हो सकती है। राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम अधिकांशतः शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, 12 दिसंबर से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से आंशिक बादल छा सकते हैं और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा : भजनलाल शर्मा

जयपुर/दक्षिण भारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध होने से यह क्षेत्र राज्य के विकास में महती भूमिका निभाता है। साथ ही, यह क्षेत्र स्थानीय रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास की भी अहम कड़ी है। हमारी सरकार प्रदेश को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनिज संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए समयबद्ध राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। साथ ही, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में असीम खनिज संपदा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की पहचान की जाए। साथ ही, अत्याधुनिक नवाचार एवं एआई का उपयोग करते हुए नए खनिज ब्लॉक्स की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि खनिज संपन्न राज्यों में खान क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं राजस्व वृद्धि के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन किया जाए जिससे राजस्व में वृद्धि की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि रोजगार को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, अवैध खनन पर अंकुश लगे। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा पुलिस, परिवहन एवं खान विभाग आपसी समन्वय कर अवैध खनन की रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन निर्धारण के लिए क्षेत्र में ड्रोन सर्वे को बढ़ाया जाए। साथ ही, खनन पट्टा क्षेत्रों एवं अवैध खनन स्थलों की जियो फैन्सिंग को और प्रभावी बनाया जाए।

व्यस्त समय में ट्रेन के पायदान पर यात्रा करना लापरवाही नहीं : उच्च न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। बंबई उच्च न्यायालय ने एक रेल दुर्घटना में चल बसे एक व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दिये जाने पर मुहर लगाते कहा कि उपनगरीय ट्रेनों में काम के सिलसिले में व्यस्त समय के दौरान यात्रा करने वाले व्यक्ति के पास ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी जान को जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, और इसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की एकल पीठ ने सोमवार को रेलवे प्रशासन की यह दलील स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह दुर्घटना उक्त व्यक्ति के लापरवाह रवैये के कारण हुई, जो ट्रेन के पायदान पर खड़ा था।

केंद्र सरकार ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के दिसंबर 2009 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया था। यह व्यक्ति 28 अक्टूबर 2005 को भयंदर से मरीन लाइन्स की ओर यात्रा करते समय ट्रेन से गिर गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। पीठ ने रेलवे की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह इस व्यक्ति की लापरवाही थी जिसकी वजह से उसकी जान गयी। पीठ ने कहा कि सुबह के समय विरार-चर्चगेट ट्रेन में बेहद भीड़ होती है और विशेषकर भायंदर रेलवे स्टेशन पर किसी भी यात्री के लिए डिब्बे में प्रवेश कर पाना बहुत कठिन होता है। उच्च न्यायालय ने कहा, ''आज भी यही स्थिति है। इसलिए यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि दरवाज़े के पास खड़े होकर यात्री लापरवाही बरत रहा है। अगर किसी व्यक्ति को अपने काम से यात्रा करनी है और डिब्बे में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, तो यात्री के पास दरवाज़े के पास खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।''

राज्यसभा के सभापति ने वंदे मातरम् पर कहा, एक राष्ट्र के रूप में साथ खड़े होने का संकल्प लें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना से देश को जोड़ने वाला ''अमर स्तुति गीत'' बताते हुए सभी से एकता और राष्ट्रीय सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया।

वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर उच्च सदन में चर्चा से पहले सभापति ने कहा कि यह गीत उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत की याद दिलाता है, जो इसे गाते हुए फांसी के तख्ते तक निर्भीकता से पहुंचे।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम् को हर घर, हर स्कूल, हर संघर्ष और हर भारतीय के हृदय तक पहुंचाया।

राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम् सिर्फ एक गीत ही नहीं है बल्कि यह हमारे राष्ट्र की धड़कन है। यह असंख्य माताओं की मौन प्रार्थना, शोषितों की आशा और स्वतंत्रता का स्वप्न देखने वालों का अटूट साहस है। उन्होंने कहा कि

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह अमर गीत औपनिवेशिक दमन के दौर में स्वतंत्रता की आकांक्षा का प्रतीक बना और इसने धर्म, भाषा और भूगोल की सीमाएं पार कर पूरे राष्ट्र को मातृभूमि-प्रेम की एक भावना में बांधा।

उन्होंने कहा, वंदे मातरम् स्वतंत्रता सेनानियों का अंतिम उद्घोष था, जिसे वे गर्व से गाते हुए फांसी पर चढ़े। उनकी बलिदान कथा इस गीत की हर पंक्ति में गूंजती है।

सभापति ने सुब्रमण्यम भारती की एक देशभक्तिपूर्ण कविता का भी उल्लेख किया।

गृह मंत्री अमित शाह को चर्चा शुरू करने की अनुमति देने से पहले राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम् एक संकल्प हैहमारी पहचान का, हमारी एकता का, और हमारी सामूहिक नियति का। इसकी रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आइये, हम सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें। उन्होंने कहा, आज हम संकल्प लेंईमानदारी से देश की सेवा करने का, एक जनता और एक राष्ट्र के रूप में साथ खड़े होने का, और गर्व से वंदे मातरम् कहने का।

राज्यसभा में 'वंदे मातरम्' पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

वंदे मातरम् पर चर्चा बंगाल में चुनावी लाभ, वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

असली देशभक्ति प्रतीकों और भाषणों में नहीं, बल्कि आर्थिक समस्याओं व सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में है। अपने लगभग एक घंटे के संबोधन में खरगे ने पड़ोसी देशों में भारत के घटते प्रभाव की बात उठाई।

नई दिल्ली/भाषा। 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में हुई बहस के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह चर्चा बंगाल चुनावों को ध्यान में रखते हुए शुरू की है और सरकार जनता की असली समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। खरगे ने कहा, भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब संसद आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर उनका समाधान करेगी। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, गिरते रुपये और सामाजिक चुनौतियों जैसे विषयों पर बहस से बचने का आरोप लगाया।

खरगे ने कहा, उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा बंगाल चुनावों को देखते हुए शुरू की है। असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असली देशभक्ति प्रतीकों और भाषणों में नहीं, बल्कि आर्थिक समस्याओं व सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में है। अपने लगभग एक घंटे के संबोधन में खरगे ने पड़ोसी देशों में भारत के घटते प्रभाव की बात उठाई। उन्होंने कहा कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में बढ़ रहा है और भारत मौन है। उन्होंने तंज किया, 56 इंच का सीना किस काम का, जब चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते? उन्होंने कहा, ''नेपाल चीन से निवेश की मांग कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश तीन तरफ़ा बैठकों में हिस्सा ले रहा है। बीजिंग अपनी रणनीतिक योजना के तहत खुलेआम दक्षिण एशिया को अपनी ओर खींच रहा है।'' रुपये के अवमूल्यन का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के कार्यकाल में डॉलर के मुकाबले रुपया 5560 के बीच था, जबकि अब 90 के पार पहुंच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के पुराने भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि पहले वे रुपये की गिरावट पर तीखी टिप्पणी करते थे। खरगे की टिप्पणियों पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। नेता सदन जे. पी. नड्डा ने कहा कि खरगे बहस के विषय से भटक रहे हैं। सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने भी खरगे से कहा कि वह विषय पर केंद्रित रहें, अन्य मुद्दों पर चर्चा बाद में की जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा नेताओं पर जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 'वंदे मातरम्' के पहले दो छंदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का निर्णय केवल नेहरू का नहीं था, बल्कि यह निर्णय महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य नेताओं की सहमति से लिया गया था।

उन्होंने कहा यह आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गाली देना और नेहरूजी को निशाना बनाना है। उनका कद कोई कम नहीं कर सकता। हम हमेशा वंदे मातरम् कहते आए हैं खरगे ने अपने संबोधन की शुरुआत वंदे मातरम के नारे से की और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा यह गीत गाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित इस गीत को 'बांटने' का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस नेता हमेशा से 'वंदे मातरम्' का उद्घोष करते रहे हैं।

बिहार में जिला,अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर एक-एक विद्यालय को 'मॉडल स्कूल' बनाया जाएगा : सुनील कुमार

पटना/भाषा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर एक-एक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से भी बेहतर होंगे। मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां जल्द से जल्द ऐसे स्कूल संचालित करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने का भी निर्देश दिया। साथ ही छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती पर अमल करने और पात्र शिक्षकों को नियमानुसार प्रोन्नति देने पर जोर दिया। कुमार ने कहा कि जिन शिक्षकों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) और अन्य भत्तों का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें इसका लाभ सुनिश्चित कराया जाए। मंत्री ने विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर विशेष बल दिया और कहा कि निरीक्षण कार्य में मुख्यालय स्तर के अधिकारी भी शामिल होंगे।

वंदे मातरम् से जुड़े धार्मिक व ऐतिहासिक मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए न हो : अरशद मदनी

नई दिल्ली/भाषा। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एएम) के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने 'वतन की पूजा' करने और 'देश से प्रेम' को अलग अलग बताते हुए जोर दिया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् से जुड़े धार्मिक और ऐतिहासिक मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संगठन द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक, इस्लाम में एकेश्वरवाद के सिद्धांत के पालन को रेखांकित करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय किसी के 'वंदे मातरम्' गीत गाने के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमें किसी के वंदे मातरम् पढ़ने या गाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम यह बात फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इस इबादत में किसी दूसरे को शरीक (भागीदार) नहीं कर सकता।

बुजुर्ग मुस्लिम नेता ने कहा कि वंदे मातरम् कविता की कुछ पंक्तियां ऐसे धार्मिक विचारों पर आधारित हैं जो इस्लामी आस्था के खिलाफ हैं, खासकर इसके चार अंतरों में देश को दुर्गा माता जैसी देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनकी पूजा के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो किसी मुसलमान की बुनियादी आस्था के विरुद्ध हैं। मदनी ने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिनके तहत किसी भी नागरिक को उसके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध किसी नारे, गीत या विचार को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, उच्चतम न्यायालय का भी यह स्पष्ट फैसला है कि किसी भी नागरिक को राष्ट्रगान या ऐसा कोई गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके धार्मिक विश्वास के खिलाफ हो। जमीयत (एएम) प्रमुख ने कहा, वतन से मोहब्बत करना अलग बात है और उसकी पूजा करना अलग बात है।

बिहार में अवैध खनन पर 10 लाख रुपये जुर्माना, सूचना देने वालों को नकद इनाम

पटना/भाषा। बिहार सरकार ने अवैध खनन और 'ओवरलोडिंग' पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को कड़े कदमों की घोषणा की। इसके तहत ऐसे कार्यों में शामिल वाहनों के मालिकों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अवैध खनन के आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। खनन एवं भूविज्ञान मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून का शासन बनाए रखने को कहा है और हम अपने हर शब्द को कार्रवाई में बदलेंगे। सरकार की नीति और मंशा स्पष्ट है। हम राज्य से अवैध खनन की प्रथा को खत्म कर देंगे।'' सिन्हा ने कहा कि विभाग ''जनभागीदारी'' के माध्यम से अवैध खनन को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि

मीडियाकर्मियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवैध खनन में शामिल वाहनों की जानकारी देने पर इनाम दिया जाएगा और यह इनाम ट्रक के लिए 10,000 रुपये और ट्रैक्टर के लिए 5,000 रुपये का होगा। उन्होंने कहा, ''इच्छा होने पर हम उन्हें 'बिहारी योद्धा' का प्रमाण पत्र भी देंगे। हालांकि उनकी सहमति के बिना उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ताकि उन्हें आपराधिक तत्वों के 'नकारात्मक प्रभाव' से बचाया जा सके।'' सिन्हा ने बताया कि खनन विभाग पुलिस और प्रशासन के सहयोग से राज्यभर में अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ छापेमारी कर रहा है। उन्होंने कहा, ''जिले के उपायुक्त, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास छापेमारी की गई, जिसमें अवैध रेत बिक्री में शामिल 28 ट्रैक्टर को जब्त किया गया।''

ऐसे समावेशी आंकड़े नहीं हैं जो वायु प्रदूषण का मौत से सीधा संबंध बताएं : स्वास्थ्य राज्य मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने राज्यसभा को बताया कि देश में ऐसे समावेशी आंकड़े नहीं हैं जिनसे वायु प्रदूषण का मौत से सीधा संबंध साबित हो सके। जाधव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उच्च सदन को बताया कि वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों और उनसे जुड़ी अन्य बीमारियों का एक प्रमुख कारक है, लेकिन स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव कई कारकों के संयुक्त परिणाम के रूप में सामने आता है। ''इनमें खान-पान की आदतें, व्यावसायिक परिस्थितियां, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, चिकित्सा इतिहास, प्रतिरक्षा क्षमता और अनुवांशिकी आदि शामिल हैं।''

जाधव ने बताया कि केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से लागू राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) के तहत जागरूकता, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी और साझेदारी बढ़ाने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। जाधव ने बताया कि कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर अद्यतन स्वास्थ्य योजना तैयार की गयी है। सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्य कार्य योजना भी बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण पर पृथक अध्याय शामिल है और इसके दुष्प्रभाव कम करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। उनके अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय समय-समय पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह जारी करता है और विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ हवा दिवस (7 सितंबर) तथा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस (2 दिसंबर) पर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर बंगालियों से नफरत करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली/भाषा। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा पर बंगालियों से नफरत करने का आरोप लगाते हुए दावा किया बांग्लाभाषी लोगों को रोहिंग्या करार देकर देश से निकाला जा रहा है, जबकि गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत मिजोरम में रोहिंग्याओं को प्रवेश दिया जा रहा है। बनर्जी ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय ने मिजोरम सरकार को बाहर से आने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति दी है। उन्होंने दावा किया कि यदि दिल्ली में कोई बांग्ला बोलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।

तृणमूल सांसद ने देश से बंगाली लोगों को रोहिंग्या करार देकर निकाले जाने का आरोप लगाते कहा, ''आज रोहिंग्या कहां आ रहा है, वह मिजोरम में आ रहा है गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत। मैं जानता हूं कि क्या समस्या है...भाजपा 'बंगाली हेटर' है, यही कारण है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ी गई और राजाराम मोहन राय की कटु आलोचना की गई थी।'' बनर्जी ने कहा कि यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री (बंकिमचंद्र चटर्जी को) 'बंकिम दा' कहते हैं। उन्होंने कहा, ''मोदी जी की तीन पीढ़ी पहले बंकिमचंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था, लेकिन वह उन्हें भी 'दादा' बोल देते हैं। वह कभी किसी गुजराती को तो 'दादा' नहीं बोलते...क्या वह (सरदार पटेल को) 'वल्लभभाई दा' बोलते हैं।''

लोकसभा में 'बंकिम दा' वाली टिप्पणी को लेकर माफी मांगें प्रधानमंत्री मोदी, यह बंगाल का अपमान : ममता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कूच बिहार/भाषा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को 'बंकिम दा' कहकर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बंगाल के सांस्कृतिक प्रतीकों और स्वतंत्रता सेनानियों का बार-बार अपमान करने का आरोप लगाया।

ममता बनर्जी ने कूचबिहार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को लापरवाही से संबोधित कर उन्हें वह सम्मान भी नहीं दिया गया, जिसके वह हकदार थे। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय गीत लिखने वाले का अपमान किया गया। आपको सिर झुकाकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए। फिर भी आपको माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान किया है। लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा चटर्जी को 'बंकिम दा' कहकर संबोधित किया जाना विवाद का विषय बन गया।

जुनून और जोश के बिना खिलाड़ी के तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते : तेंदुलकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार को कहा कि युवा खिलाड़ी जुनून और जोश के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने युवाओं को 'मुश्किल चुनौतियों का सामना करने' और दूसरों के लिए मिसाल कायम करने की सलाह दी। तेंदुलकर ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें क्रिकेट से इतना अधिक लगाव था कि वह इस खेल में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करने को भी तैयार रहते थे। उन्होंने कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों में लगभग दो महीने तक रोजाना 12 घंटे तक अभ्यास करते थे।

तेंदुलकर ने 'इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आईएसपीएल)' के तीसरे सत्र की नीलामी से पहले कहा, ''मैंने क्रिकेट खेलना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझमें जुनून था। मुझे इस खेल से बेइंतहा प्यार था और मैं बस भारत के लिए खेलना चाहता था। मैं इसके लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था।'' उन्होंने कहा, ''मेरे जीवन में कई पड़ाव आए। इसमें स्कूल क्रिकेट भी था और मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार था। एक दौर ऐसा भी था जब मैंने गर्मी की छुट्टियों में लगातार 55 दिनों तक 12 घंटे अभ्यास किया और आखिरकार मैं बीमार पड़ गया। अगर जुनून और जोश नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।'' तेंदुलकर ने कहा कि एक खिलाड़ी के विकास के लिए कई चीजों का एक साथ आना जरूरी है, लेकिन सही समय पर अच्छा प्रदर्शन करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा, '' आपको आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत, योजना, उसे लागू करने की क्षमता, सही मार्गदर्शन और अनुशासन की जरूरत होती है।''

मतदाता सूचियों की शुद्धता के लिए एसआईआर जरूरी, कांग्रेस के शासन में कई बार हुई : मेघवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मतदाता सूचियों की शुद्धता के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जरूरत बताते हुए मंगलवार को कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में छह से सात बार यह प्रक्रिया लागू की गई थी। मेघवाल ने लोकसभा में 'चुनाव सुधारों पर चर्चा' में कहा कि बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और आज उसी के आधार पर एसआईआर की जा रही है जिसके अनुसार पात्र मतदाता रहें और अपात्र लोगों के नाम हट जाएं।

मेघवाल ने कहा, ''यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग समय-समय पर एसआईआर करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। कांग्रेस के समय कितनी बार एसआईआर हुई। वो करें तो ठीक,

हम करें तो खराब। यह कैसा विरोधाभास है।'' उन्होंने कहा, ''स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूचियों की शुद्धता और अखंडता बनाये रखना आवश्यक है। इसके लिए समय-समय पर गहन पुनरीक्षण और समरी (संक्षिप्त) पुनरीक्षण किये जाते हैं और दोहरी प्रविष्टि हटाकर पारदर्शिता लाई जाती है।''

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों के लोग निर्वाचन आयोग की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, लेकिन यहां उसके खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि यह कैसा विरोधाभास है।

मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस के समय छह से सात बार एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और आखिरी बार यह कवायद 2002 में हुई थी। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग दो दशक से अधिक समय में तेजी से शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन एवं विस्थापन आदि के कारण इस प्रक्रिया की अब जरूरत समझी गई। उन्होंने एसआईआर की आलोचना और विरोध के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ''चुनावों में बार-बार हार ने विपक्ष को हताशा से भर दिया है। इनके पास कोई बहाना नहीं है इसलिए कभी ईवीएम में, कभी एसआईआर में इन्हें गड़बड़ी दिखती है। सच यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती। इसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इसके नेता चुनाव सुधारों को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते हैं लेकिन विपक्षी दल के लोग आजादी के बाद से ही 'वोट चोरी से बाज नहीं आए।''

सुविचार

लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

राजनीतिक परिपक्वता दिखाएं

विपक्ष के एक सांसद ने लोकसभा में एसआईआर और ईवीएम के बारे में जो सवाल उठाए हैं, वे नए नहीं हैं। कुछ राजनेताओं को एसआईआर से क्या समस्या है? क्या मतदाता सूची को शुद्ध नहीं करना चाहिए और जैसा चल रहा है, वैसा भविष्य में भी चलता रहना चाहिए? लोग समय-समय पर अपने दस्तावेज बनवाते हैं; पुराने दस्तावेजों को ठीक करवाते हैं; मकान, दुकान, फर्नीचर को दुरुस्त करवाते हैं; मोबाइल फोन में ऐप अपडेट करते हैं ... क्या इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदाता सूची को ठीक नहीं करना चाहिए? इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जो राजनेता एसआईआर की बुराई करते दिखाई दे रहे हैं, वे भी जानते हैं कि यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। वोटबैंक की राजनीति के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता! बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाया गया था। महागठबंधन के नेताओं ने 'वोटचोरी', 'लोकतंत्र का खात्मा' जैसे मुद्दों को हवा दी थी, जिन्हें तालियां खूब मिलीं, बस उतने वोट नहीं मिले। अब कोई भी राजनेता यह न समझे कि जनता को उससे कम जानकारी है। आज सबके पास मोबाइल फोन है। किस पार्टी ने कब, कौनसे वादे किए थे और क्या कारनामे किए थे – यह आसानी से मालूम किया जा सकता है। पिछले दशकभर में चुनावी हार के बाद ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने का चलन बहुत देखा गया है। अगर जीत गए तो यह शीर्ष नेतृत्व का कमाल है, अगर हार गए तो ईवीएम खराब है! खुद की गलतियों पर पर्दा डालने का यह अच्छा बहाना है। कुछ राजनेता इससे भी आगे बढ़कर यह मांग करते हैं कि मतपत्रों से चुनाव कराएं।

उनके 'समर्थक' भी हां में हां मिलाते हुए कहते हैं कि मतपत्रों का दौर आ जाएगा तो सारे झगड़े ही मिट जाएंगे। नागरिकों, खासकर युवाओं को मालूम होना चाहिए कि मतपत्रों के जमाने में चुनावी विवाद कम नहीं थे। अगर वही व्यवस्था वापस लागू कर दी जाए तो उससे झगड़े कम नहीं होंगे, बल्कि कई गुणा बढ़ेंगे। ज्यादा दूर न जाएं, इंटरनेट के जरिए अस्सी और नब्बे के दशक में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं पढ़ लें। उस जमाने में कई बूथों पर कब्जा कर मतपत्रों पर फर्जी ठप्पे लगा दिए जाते थे। जहां कार्यकर्ता भिड़ते, वहां मतपत्र या पेटी पर धावा बोला जाता था। कहीं मतपत्र फाड़ दिया जाता, कहीं पेटी को ही उड़ा ले जाते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो पेटी में बाल्टी भरकर पानी डाल देते थे। अगर यह भी न होता तो मतगणना के दौरान जरूर हंगामा होता था। किसी मतपत्र पर ठप्पा जरा-सा इधर-उधर लगा कि बखेड़ा खड़ा हो जाता था। ऐसे मतपत्र एक नहीं, अनेक होते थे। इस झगड़े में मतगणना कर रहा कर्मचारी पिसता था। उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते थे, भीड़ हंगामा करने लगती थी। अगर किसी जगह मतपत्रों और डाले गए कुल वोटों का आंकड़ा नहीं मिलता था तो 'वोटचोरी' के आरोप लगते थे। हर मतगणना केंद्र पर कई मतपत्र इस वजह से खारिज करने पड़ते थे, क्योंकि ठप्पा सही जगह नहीं लगा था। जो उम्मीदवार हारता, वह शिकायत करता था कि 'मैं तो जीत रहा था, बस मतपत्रों में गड़बड़ हो गई, मेरे वोट चोरी हो गए।' ऐसे मामले अदालतों में जाते थे। अब तो मतगणना वाले दिन दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाती है। अगर कुछ सीटों पर विवाद की स्थिति होती है तो ईवीएम से गणना में ज्यादा समय नहीं लगता। पहले, मतपत्रों की गणना में ही कई दिन लग जाते थे। यह वो दौर था, जब भारत में कुल मतदाता 60 करोड़ से कम थे। आज 99 करोड़ से ज्यादा हैं। ऐसे में मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग कितनी उचित है? नेतागण विवेक एवं बुद्धिपूर्वक विचार करने के बाद कोई मुद्दा उठाएं। कुछ राजनीतिक परिपक्वता दिखाएं।

ट्वीटर टॉक

तीन दिन पहले भाजपा सरकार के कृषि मंत्री ने बयान दिया कि प्रदेश में पर्याप्त यूरिया उपलब्ध है। यदि पर्याप्त यूरिया उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है जिसमें किसान लाइनों में परेशान हो रहे हैं? क्या पर्याप्त यूरिया उपलब्धता का दावा केवल बयानों तक सीमित है?

-अशोक गहलोत

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक और उपयोगी चर्चा हुई। लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने तथा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर कार्य करने के विषय में विचार अत्यंत मार्गदर्शक रहे।

-दिया कुमारी

आज भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सुना। समाधान के लिए यथासंभव, व्यवहार्य और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

-किरोड़ीलाल मीणा

प्रेरक प्रसंग

आशीर्वाद का मर्म

एक बार एक राजा के दरबार में राजकवि ने प्रवेश किया। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। राजकवि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, 'आपके शत्रु चिरंजीव हो।' यह आशीर्वाद सुनकर राजा राजकवि से नाराज हो गए। राजकवि को इस बात का भान हो गया कि राजा उनकी बात सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, 'महाराज! मैंने आपको आशीर्वाद दिया पर आपने लिया नहीं।' राजा ने कहा, 'कैसे लूं मैं आपका आशीर्वाद आप मेरे शत्रुओं को मंगलकामना दे रहे हैं।' इस पर राजकवि ने समझाया, 'राजन! मैंने आपका हित ही चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी। सावधानी तभी बनी रह सकती है, जब शत्रु का भय हो। उसके न रहने पर हम निश्चिंत हो जाते हैं। हे राजन! मैंने आपके शत्रुओं की नहीं, आपकी ही मंगल कामना की है।' राजकवि के आशीर्वाद का मर्म जानकर राजा संतुष्ट हो गए।

सामयिक

गोवा का नाइट क्लब लाक्षागृह कैसे बन गया?

मनोज कुमार अग्रवाल

मोबाइल : 9219179431

गोवा की हसीन दिलकश विदेशी कल्चर की पर्याय अरपोरा में रविवार तड़के बीच वे रोमियो लेन नाइटक्लब में लगी भीषण आग में मारे गए सभी 25 पीड़ितों की पहचान कर ली गई है। अधिकारियों ने रविवार देर रात मृतकों की सूची जारी की। मृतकों में 20 नाइटक्लब के स्टाफ थे जबकि 5 पर्यटकों ने भी इस हादसे में जान गंवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो पांच पर्यटक हादसे में मारे गए, उनमें चार दिल्ली के रहने वाले है जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल है. पांचवां पर्यटक कर्नाटक का निवासी है।

आपको पता रहे इस दुःखद हादसे में 25 लोगों की जान चली गयी है। इस हादसे से सभी लोग काफी मर्माहत है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी है, क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि हमारे सिस्टम में छिपे भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक जीता जागता सबूत है। जिन निर्दोष लोगों की जान चली गई उनमें पर्यटक भी थे, कर्मचारी भी। कई परिवार उजड़ गए, कई सपने चंद मिनटों में राख हो गए। सवाल यह नहीं है कि आग कैसे लगी, बल्कि यह है कि आग लगने की नौबत आई ही क्यों? इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे देश में सुरक्षा नियमों की चिंता तब होती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। सरकार और प्रशासन की आंख तब खुलती है, जब कई जानें जा चुकी होती हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना पर दुख जताया, मौके का दौरा किया, जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन यह सारा कुछ बहुत देर होने के बाद हुआ।

आप जानते हैं कि गोवा एक पर्यटन राज्य है, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं। ऐसे में वहां चल रहे क्लबों, पब्स और बार्स की सख्त सुरक्षा जांच होना ही चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कई जगह बिना अनुमति चल रही हैं, कई संरचनाएं अवैध तरीके से बनाई गई हैं और कई जगह अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन तक नहीं होता। अर्पोरा-नागोआ पंचायत ने खुद चताया कि यह क्लब बिना निर्माण अनुमति के खड़ा किया गया था। अगर यह तथ्य पहले से ज्ञात था, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन की यह ढिलाई ही इस हादसे की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। यह लापरवाही सिर्फ क्लब मालिकों की नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की भी है, जो नियमों को लागू करने में नाकाम रहे। जब सरकार खुद स्वीकार करती है कि क्लब सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहा था, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? प्रारंभिक जांच बताती है कि क्लब ने फायर सेफ्टी के बुनियादी नियमों तक का पालन नहीं किया गया था। नाइटक्लब में उपस्थित लोगों का कहना है कि कोई स्पष्ट आपातकालीन निकास मार्ग दिखाई नहीं देता था, आग लगते ही बिजली काट दी गई, जिससे अंधेरे में भगदड़ मच गई। सबसे बड़ी बात कि फायर अलार्म व स्प्रिंकलर जैसे उपकरण या तो मौजूद ही नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे। चश्मदीदों के अनुसार आधी रात के बाद अचानक आग लगी और उस समय क्लब में भीड़ बहुत अधिक थी और करीब 100 लोग डांस कर रहे थे। बाहर जाने के रास्ते बहुत संकरा और कम था। अंदर की सजावट में ताड़ के पत्तों और हल्की चीजों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग ने और विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही लोग भागने लगे और स्थिति और बिगड़ गई और कुछ लोग घबराहट में गलत दिशा में भागते हुए सीधे रसोईघर में फंस गए। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि क्लब की ओर जाने का रास्ता बहुत संकरा था और इस कारण दमकल की गाड़ियों को करीब 400 मीटर दूर रुकना पड़ा, जिससे बचाव कार्य देर से शुरू हुआ। अधिकतर लोगों की मौत धुआं भरने और सांस न ले पाने के कारण हुई। अर्पोरा नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर के अनुसार यह क्लब बिना निर्माण अनुमति के बनाया गया था। जांच में पाया गया कि क्लब के पास निर्माण की अनुमति नहीं थी। पंचायत ने तोड़फोड़ का आदेश दिया था, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। क्लब का संचालन सौरभ लूथरा द्वारा किया जा रहा था और उनके भूमि मालिकों और साझेदारों से विवाद भी चल रहा था।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वयं स्वीकार किया कि क्लब सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहा था। जब सरकार का मुखिया भी यह स्वीकार करता है, तब सवाल खड़ा होता है, अगर बलब गलत थे, तो उन्हें इतने लंबे समय तक चलने दिया किसने? क्या स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, पर्यटन विभाग और फायर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या नियमों की जांच सिर्फ कागजों पर पूरी कर ली जाती है? यह त्रासदी केवल मालिकों की लापरवाही नहीं, बल्कि एक व्यापक सिस्टम फेलियर का है।

गोवा पर्यटन को भारत का 'फेस' माना जाता है। साल भर लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटक वहां आते हैं, और नाइटलाइफ पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। होटल, बार, शैक्स और क्लब करोड़ों रुपये कमाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा और नियमों का पालन पर्यटन की कीमत पर तिलांजलि दी जा सकती है?

गोवा में कई बार यह आरोप लगता रहा है कि नाइटलाइफ प्रतिष्ठानों को 'लाइसेंस देने में उदारता और निगरानी में लापरवाही बरती जाती है। यह मॉडल तभी तक चलता है जब तक कोई बड़ा हादसा सामने न आ जाए और अब वह हादसा हो चुका है। अगर देखा जाए तो यह सिर्फ गोवा की घटना नहीं, भारत के हर बड़े शहर में मौजूद खतरों का संकेत है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु या कोलकाता हर जगह अवैध क्लब, खराब वेंटिलेशन, खराब निकासी रास्ते और ज्वलनशील सजावट आम होती जा रही है। हम हर बार हादसे के बाद जागते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सब भूल जाते हैं। इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। 25 लोग इस लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुका चुके हैं। यह समय है, जब सरकार को सिर्फ जांच और कार्रवाई की बात नहीं, बल्कि असली बदलाव लाना होगा, ऐसे बदलाव जो भविष्य में किसी भी क्लब, होटल या मॉल में इस तरह की त्रासदी होने से रोक सकें। नाइटलाइफ पर्यटन का हिस्सा है, लेकिन पर्यटन की सुरक्षा उससे भी बड़ा मुद्दा है। यदि पर्यटक और स्थानीय लोग खुद को सुरक्षित न महसूस करें, तो किसी भी पर्यटन राज्य की चमक फीकी पड़ जाएगी। गोवा का नाइटक्लब हादसा हमें याद दिलाता है कि चमक-दमक से भरी जगहों के पीछे कितनी लापरवाहियां छिपी रहती हैं। यह घटना सिर्फ एक क्लब या एक शहर की समस्या नहीं है, यह हमारी व्यवस्था, हमारे प्रशास और हमारी सुरक्षा सोच की गहरी खामियों का आईना है। सरकार को अब नींद से जागना ही होगा। नियमों को कड़ाई से लागू करना होगा और अवैध कारोबार को बंद करना होगा। सबसे जरूरी बात है कि लोगों की जान को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जिंदगी की कीमत किसी भी क्लब, किसी भी व्यवसाय या किसी भी चमक-दमक से कहीं ज्यादा होती है। इस हादसे ने हमें यह याद दिलाया है कि चमकती रोशनी, तेज संगीत और ग्लैमर के पीछे अक्सर एक खतरनाक लापरवाही छिपी होती है। यह त्रासदी एक चेतावनी की तरह है। सुरक्षा सिर्फ कागहों पर नहीं, जमीन पर भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। हमारी सरकार, प्रशासन और व्यापारियों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई क्लब, रेस्टोरेंट या पब्लिक स्पेस इस तरह की लापरवाही का शिकार न हो। इस घटना से सबक लेना जरूरी है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, नियमों को कड़े रूप में लागू किया जाना चाहिए और किसी भी क्लब को सुरक्षा मानकों की अनदेखी की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हर कीमत पर यह सुनिश्चित करना होगा कि गोवा का हर पर्यटक, हर देसी विदेशी नागरिकों का जीवन सुरक्षित रहे।

हर हादसे के बाद जांच की लकीर खींची जाती है जांच कमेटी गठित की जाती हैं लेकिन इन जांच कमेटी की रिपोर्ट्स को रद्दी की टोकरी या फाइलों में दबा दी जाती है और हर बार जांच का नाटक कर नए हादसों का इंतजार किया जाता है।

नजरिया

इंटरनेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी इनिशिएटिव फॉर साइंस (आईबीबीआईएस) जैसे संगठन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। यह संगठन शिक्षा जगत, उद्योगों, सरकारों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। विभिन्न देशों ने जैव सुरक्षा के नियम एवं विनियम बनाए हैं।

वैश्विक स्तर पर जैविक आतंकवाद का बढ़ता खतरा

ज्ञान चंद पाटनी

मोबाइल : 9784542209

बायोटेररिज्म यानी जैविक आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जिसमें जीवाणु, वायरस, विषैले पदार्थ या अन्य जैविक एजेंटों का इस्तेमाल इंसानों, पशु-पक्षियों या फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह पारंपरिक आतंकवाद से बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि जैविक एजेंट हवा, पानी, खाद्य पदार्थों या सीधे संपर्क से तेजी से फैल सकते हैं तथा लोगों का जीवन प्रभावित कर सकते हैं। जैविक आतंकवाद को आधुनिक समय का सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। जीवाणुओं और विषाणुओं का इस्तेमाल करके एंथ्रेक्स, प्लेग, बोटुलिज्म, टूलेरिया, ग्लैंडर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाई जा सकती हैं। आतंकवाद के बढ़ते उग्र स्वरूप और जैव प्रौद्योगिकी में हो रहे विकास ने इस खतरे को और अधिक गंभीर बना दिया है। कुछ आतंकवादी संगठन, सिरफिरे लोग तथा तानाशाह इन जैविक हथियारों को हासिल करने और उनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खतरा इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जैविक हमलों का पूर्वानुमान लगाना और प्रतिक्रिया देना मुश्किल होता है।

जैविक आतंकवाद के सबसे संभावित एजेंट जीवाणु, विषाणु और टॉक्सिन होते हैं। जैसे एंथ्रेक्स जैसी बीमारी बैसिलस एंथ्रासिस नामक बैक्टीरिया से होती है, जो अधिकतर पशुओं में पाया जाता है, लेकिन इंसानों में भी संक्रमण फैला सकता है। इसी तरह प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। प्लेग के लिए इसका उपयोग जैविक हथियार के रूप में हो सकता है क्योंकि यह महामारी तेजी से फैल सकती है। इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नामक बैक्टीरिया से पैदा होने वाला टॉक्सिन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर व्यक्ति को अपाहिज बना देता है। यह दुनिया के सबसे घातक विषाक्त पदार्थों में से एक माना जाता है। टूलेरिया रोग फ्रांसिसेला टूलारेन्सिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है, जो त्वचा, फेफड़ों और लसीका तंत्र को प्रभावित कर सकती है। रिकेट्सिया बैक्टीरिया विशेष प्रकार के कीटों के माध्यम से फैलते हैं। ये बुखार, रक्ताल्पता और कई गंभीर बीमारियां जन्म देते हैं। वायरस के जरिए चेचक जैसी बीमारियां फैलाई जा सकती हैं। ये वायरस जानलेवा संक्रामक होते हैं और जैविक हथियार के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इस तरह के जैविक एजेंटों का प्रयोग करके आतंकी संगठन इंसानों को संकट में डाल सकते हैं। जैविक हथियारों का खतरा कपोलकल्पित नहीं है। इतिहास में जैविक हथियारों का प्रयोग भी दर्ज है। उदाहरण के लिए, मध्यकालीन युग में तुर्की और मंगोल सैनिक संक्रमित पशुओं के शवों को शत्रु नगरों में फेंक कर बीमारी फैलाने की कोशिश करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चीन के खिलाफ इस तरह का प्रयोग किया था। आधुनिक काल में जैविक आतंकवाद का सबसे चर्चित मामला 2001 में अमेरिका में एंथ्रेक्स के संक्रमण का है। संक्रमित पत्रों के माध्यम से एंथ्रेक्स फैलाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद जैविक सुरक्षा और जैव आक्रमण से रक्षा की तरफ विश्व का ध्यान एक बार फिर गया। हालांकि, आतंकी संगठनों द्वारा जैविक हथियारों के इस्तेमाल के मामले अब भी दुर्लभ हैं, लेकिन आतंकी संगठनों और कुछ राष्ट्रों पर जैविक हथियारों के विकास और संभावित प्रयोग का संदेह हमेशा बना रहता है। कोरोना वायरस महामारी के बाद जैविक आतंकवाद को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ी है। अब संक्रामक रोगों को महामारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के जोखिम को समझा जाने लगा है।

जैविक आतंकवाद के हमले से दुनिया को होने वाले नुकसान का ठीक-ठीक आकलन भी कठिन है क्योंकि इसके प्रभाव लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। जैविक हथियारों से जान का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर भी गहरा असर पड़ता है। घायल या बीमार व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक हो सकती है कि अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाए। केवल जैविक एजेंटों के फैलने की क्षमता ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही उन्नत तकनीकों के शैतानी इस्तेमाल की आशंका भी बनी हुई है। जैविक आतंकवाद मानवता के लिए एक गहरा और जटिल खतरा है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही जैविक हथियार संधि (बीडब्ल्यूसी) की 50वीं वर्षगांठ से जुड़े सम्मेलन के अवसर पर जैविक आतंकवाद के मसले को उठाया और कहा कि यह एक गंभीर खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके लिए पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को तैयार रहना होगा। उन्होंने ग्लोबल बायोसिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाने और उसे मजबूत करने की अपील की। बीडब्ल्यूसी को प्रभावी बनाए रखने के लिए संधि को आधुनिक विज्ञान और वैश्विक क्षमताओं के अनुरूप अपडेट करना आवश्यक हो गया है।

जैविक हथियार संधि (बीडब्ल्यूसी) एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 1975 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, हस्तांतरण और उपयोग को पूरी तरह से रोकना है। यह संधि जैविक हथियारों के विकास और उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। बीडब्ल्यूसी ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक नैतिक और कानूनी लाइन खींची है और संदेश दिया है कि बीमारी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पचास वर्ष बाद भी बीडब्ल्यूसी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रणालीगत खामी है। जैसे कि इसमें कोई प्रभावी अनुपालन तंत्र नहीं है, कोई स्थायी तकनीकी निकाय नहीं है और नए वैज्ञानिक विकास को ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से आधुनिक जैविक आतंकवाद के खतरों से निपटना कठिन हो रहा है।

आधुनिक विज्ञान और तकनीक, जैसे जीन संपादन, संश्लेषण जीव विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जैविक हथियारों के निर्माण को आसान और अधिक खतरनाक बना दिया है। इस तकनीकी प्रगति के साथ, जैविक आतंकवाद के खतरे में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब आतंकी समूह भी आसानी से जैव हथियार विकसित कर सकते हैं। इसलिए जैविक सुरक्षा और निगरानी प्रणालियां अत्यंत आवश्यक हो गई हैं। इस संदर्भ में बीडब्ल्यूसी की एक और बड़ी कमजोरी है कि इसमें देशों के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निरीक्षण तंत्र नहीं है। पारदर्शिता, आकस्मिक निरीक्षण और उल्लंघन पर दंड का अभाव इसे कमजोर बनाता है।

यह एक अच्छी बात है कि इंटरनेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी इनिशिएटिव फॉर साइंस (आईबीबीआईएस) जैसे संगठन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। यह संगठन शिक्षा जगत, उद्योगों, सरकारों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। विभिन्न देशों ने जैव सुरक्षा के नियम एवं विनियम बनाए हैं, कठिन सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया है। इनमें खतरे के निगरानी, जल्दी पहचान और उपचार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं। जाहिर है इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास जरूर हुए हैं लेकिन ये नाकाफी हैं। यह केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा है। इसलिए सभी देशों को मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए ऐसी प्रभावी रणनीति बनानी होगी, जो आधुनिक तकनीकी नियंत्रण, कड़े नियमों, जागरूकता, शोध एवं वैश्विक सहयोग पर आधारित हो। तब ही हम इस खतरे से सुरक्षा सुनिश्चित कर मानवता की रक्षा कर सकेंगे।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 या 21 साल करने का शिवसेना का सुझाव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। शिवसेना ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता जताते हुए सभी चुनावों के लिए 'एकल मतदाता सूची' और 'रिमोट वोटिंग' का अधिकार सुनिश्चित करने की सरकार से मंगलवार को मांग की। उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 18 साल या 21 साल करने का भी सुझाव दिया।

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने चुनाव सुधारों को लेकर लोकसभा में जारी चर्चा के दौरान कहा कि चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार की ओर से किये जा रहे सभी प्रयास उचित दिशा में हैं और इनमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शामिल हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 साल से घटाकर 18 या 21 साल करने का सुझाव दिया और कहा कि जब 18 साल की आयु प्राप्त करने के बाद मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो फिर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल या 21 साल करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', सभी चुनावों के लिए 'एकल मतदाता सूची' और अपने मतदान केंद्र से दूर बैठे मतदाता को वहीं से मत डालने की व्यवस्था करने का भी सरकार को सुझाव दिया।

शिंदे ने चुनाव में धांधली के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी को दोषी ठहराये जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ''जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सत्ता के लिए संविधान का गला घोट दिया, उसी पार्टी के लोग आज संविधान लेकर घूम रहे हैं और इसकी दुहाई दे रहे हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में मतदान पेटियों में तेजाब डालकर मतपत्रों को नष्ट किया जाता था। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से इसलिए दिक्कत है, क्योंकि वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।

शिंदे ने कहा कि वह शिवसेना (उबाठा) के सदस्य का वक्तव्य सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का वोट का अधिकार छीन लिया था, आज शिवसेना (उबाठा) के लोग उसी ओर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने से इन राजनीतिक दलों को दिक्कत है क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है।

सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सदस्य अरुण भारती ने भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 'बूथ कैप्चरिंग' आम बात थी। उन्होंने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार के दौरान राज्य में मतपत्र लूट की घटनाएं आम थीं। उन्होंने संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर को कथित तौर पर चुनाव में हराने के लिए तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की आलोचना की और कहा कि बाबासाहेब के अपमान के कारण ही कांग्रेस अभिशप्त हो गयी है और वह बिहार में 'एकल अंक' में सिमट गयी है।

संसद भवन

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और गौरव गोगोई के साथ संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान।

मोना सिंह, कुणाल रॉय ने 'थोड़े दूर थोड़े पास' पर कहा- सोशल मीडिया के युग में यह सीरीज प्रासंगिक है

मुंबई/भाषा

अभिनेत्री मोना सिंह और अभिनेता कुणाल रॉय कपूर का कहना है कि उन्हें अपनी नई सीरीज़ थोड़े दूर थोड़े पास की विषयवस्तु से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ जो यह बताती है कि प्रौद्योगिकी ने आपसी संबंधों को कैसे प्रभावित किया है। यह सीरीज मेहता परिवार की कहानी पर आधारित है, जिसके मुखिया पंकज कपूर अपने परिवार को छह महीने का 'डिजिटल डिटॉक्स' अपनाने की चुनौती देते हैं और इसके बदले उन्हें नकद इनाम की पेशकश करते हैं। 'जी5' की पांच भागों वाली इस सीरीज को शीर्षक एस. आनंद ने लिखा है और इसके निर्देशक अजय भुइयां हैं। सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''हमने वह सब देखा है (सोशल मीडिया से पहले का दौर और उसके बाद का दौर)।

यह 100 फीसदी पुरानी यादें ताजा करने वाला है। इस शो के लिए मैंने शुरू में ही हां कह दी थी।'' सीरीज में सिंह के पति की भूमिका निभा रहे कुणाल रॉय कपूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह कहानी उनके अपने घर सहित हर घर के लिए प्रासंगिक है।

अभिनेता ने कहा, मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि उनके लिए अपने उपकरण छोड़ देना क्या मायने रखता है। मतलब, उनके लिए एक समय सीमा तय करनी पड़ती है, खासकर परीक्षा के दौरान, नहीं तो लोग लगातार अपने उपकरण पर लगे रहते हैं। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी एक तरह से आपका सह अभिभावक बन जाती है और आपको यह तक पता नहीं होता कि वह अभिभावक उन्हें क्या बता रहा है। आपको यह नहीं पता कि दुनिया के किस हिस्से से कौन उन्हें क्या जानकारी दे रहा है, या कहीं वे कट्टरपंथ की ओर तो नहीं धकेले जा रहे। यह वाकई डराने वाली स्थिति है। रॉय कपूर ने कहा कि यह सीरीज़ स्क्रीन से ब्रेक लेने की बात करती है।

अरिजीत सिंह का नया रोमांटिक ट्रैक 'फितरतें' रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

संगीत की दुनिया में अरिजीत सिंह वह नाम है, जिसकी आवाज लोगों के दिलों तक सीधे पहुंचती है। चाहे दर्द भरा गीत हो या रोमांटिक, वह हर गाने में ऐसी गहराई जोड़ देते हैं, जो सुनने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेती है। इसी वजह से उनकी हर नई रिलीज को लेकर दर्शकों में अलग ही उत्सुकता रहती है। इसी कड़ी में अरिजीत सिंह का नया रोमांटिक ट्रैक 'फितरतें' रिलीज हो गया है। यह गाना रिलीज होते ही लोगों का ध्यान खींच रहा है। 'फितरतें' को मंगलवार को टाइम्स म्यूजिक ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया। गाने की कंपोजिशन रौनक फुकन ने संभाली है, जबकि इसके बोल सैयद आमिर हुसैन और सोहम मजूमदार ने लिखे हैं। दोनों ने मिलकर ऐसे शब्दों का ताना-बाना बुना है, जो प्यार, तड़प और उम्मीद को सहज तरीके से व्यक्त करते हैं। गाने के वीडियो में सनम जौहर और कनिष्का कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

अभिनेता सनम जौहर ने इस गाने का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, ''अरिजीत सिंह का गाना करना हर किसी कलाकार के लिए एक बड़ा मौका होता है। उनकी आवाज साधारण से साधारण भावना को भी बेहद खास और यादगार बना देती है। 'फितरतें' पूरी तरह रोमांस पर आधारित गाना है और जब इसे अरिजीत जैसे गायक गाते हैं, तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। मैं टाइम्स म्यूजिक के साथ दोबारा काम करने को लेकर भी उत्साहित हूं।'' वहीं अभिनेत्री कनिष्का कपूर भी इस गाने को लेकर उतनी ही भावनात्मक नजर आईं।

वोटर रोल

कोलकाता के सोनागाछी इलाके में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैंप में लोग मंगलवार को नाम लिखवाते हुए।

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के जूड पिजूष गोम्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान।

राजनीतिक कारणों से हवाई क्षेत्र का बंद होना पूरी तरह अस्वीकार्यः आईएटीए प्रमुख

जिनेवा/भाषा। वैश्विक एयरलाइंस निकाय आईएटीए के प्रमुख विली वॉल्श ने मंगलवार को कहा कि राजनीतिक कारणों से हवाई क्षेत्र को बंद किया जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और यह सभी विमानन कंपनियों के लिए खुला होना चाहिए।

वॉल्श ने यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान द्वारा एक-दूसरे की उड़ानों के लिए अपने-अपने हवाई क्षेत्र बंद करने के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर की। उन्होंने पीटीआई-भाषा के एक सवाल पर कहा, ''हम देख रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से हवाई क्षेत्र बंद किए जा रहे हैं, और स्पष्ट रूप से ऐसा होना हमारे लिए अस्वीकार्य है।''

हालांकि आईएटीए के महानिदेशक ने अपने जवाब में किसी भी देश का जिक्र नहीं किया। दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में भी वायु क्षेत्र प्रतिबंध लागू हैं।

भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद 30 अप्रैल से पाकिस्तान की एयरलाइंस एवं परिचालकों द्वारा संचालित, स्वामित्व वाली या पट्टे पर ली गई उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इसके बाद से ये प्रतिबंध बढ़ाए जाते रहे हैं। पाकिस्तान ने भी भारतीय विमान कंपनियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रखा है।

वॉल्श ने उम्मीद जताई कि प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र उड़ानों के संचालन के लिए दोबारा खोले जाएंगे और एयरलाइंस उनका इस्तेमाल कर सकेंगी।

वॉल्श ने कहा कि अगले साल एयरलाइंस प्रति यात्री औसतन सिर्फ 7.90 अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाएंगी, जबकि एप्पल सिर्फ एक आईफोन कवर बेचकर इससे ज्यादा कमाई कर लेगी। यह उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग स्तर पर एयरलाइन कंपनियों का मुनाफा अब भी बेहद मामूली है। उन्होंने आगे कहा, ''एयरलाइंस लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर अपार मूल्य बनाती हैं। वे उस मूल्य शृंखला के केंद्र में हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग चार प्रतिशत को आधार देती है और 8.7 करोड़ नौकरियों को सहारा देती है।'' उन्होंने कहा कि इसके बावजूद एक यात्री पर एयरलाइंस को औसतन 7.90 डॉलर मिलेंगे, जबकि उससे ज्यादा एप्पल सिर्फ एक आईफोन कवर बेचकर कमा लेगी।

वैश्विक एयरलाइन उद्योग हाल के वर्षों में अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनमें आपूर्ति शृंखला की समस्याएं, विमान आपूर्ति में देरी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं शामिल हैं।

वॉल्श ने यह भी कहा कि एयरलाइन उद्योग को आने वाले आठ वर्षों तक आपूर्ति शृंखला की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि विमान आपूर्ति में पहले ही कम से कम 5,300 विमानों की कमी है और एयरलाइंस की लागत भी बढ़ रही है।

वॉल्श पहले भी विमान इंजन निर्माताओं के भारी मुनाफे और एयरलाइंस के कम मार्जिन पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस आपूर्ति शृंखला से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी विकल्पों का भी मूल्यांकन कर रही हैं।

आपूर्ति शृंखला की स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि अगर कोई एयरलाइन आज विमान का ऑर्डर दे, तो उसे विमान मिलने में करीब 6.8 साल लगेंगे, और कुल बकाया ऑर्डर 17,000 से अधिक है।

स्वागत

बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर में एक कार्यक्रम में स्वागत किया गया।

यहां कोई रोडमैप नहीं, रोलरकोस्टर है : प्राजक्ता कोली

मुंबई/एजेन्सी

यूट्यूबर और एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली ने साफ कहा है कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का दौर न तो खत्म हुआ है और न ही धीमा पड़ा है, बल्कि पिछले दस साल में यह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, तेज और अनिश्चित हो गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया अब इन्फ्लुएंसर-डॉमिनेटेड हो गया है और कंटेंट क्रिएटर्स की शेल्फ लाइफ खत्म हो रही है, तो प्राजक्ता ने कहा, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। यह कम नहीं हुआ है, बस बदल गया है। दस-ग्यारह साल पहले जब हमने काम शुरू किया था, तब सिर्फ लॉन्ग-फॉर्म वीडियो चलते थे। आज लोगों का अटेंशन बस बंट गया है। आज कई नए-नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। प्राजक्ता ने साल 2017 के डिजिटल बूम को गेम-चेंजर बताया। उन्होंने कहा, उसी बूम की वजह से आज भारत में इतना काम है कि पहले से कहीं ज्यादा क्रिएटर्स मौजूद हैं। यही कारण है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकॉनमी बन चुका है। हर बड़ा ब्रांड, हर बड़ी कंपनी भारत की तरफ देख रही है और हमारे साथ काम करना चाहती है। क्रिएटर बनने की जर्नी को उन्होंने पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल बताया। प्राजक्ता ने कहा, इस इंडस्ट्री में कोई तय रोडमैप या ब्लूप्रिंट नहीं होता। यह एक रोलरकोस्टर राइड है। कभी लगता है कि तीन-चार अच्छे वीडियो बन गए, जिंदगी सेट हो गई। फिर पांचवां वीडियो आते-आते सब बदल जाता है। इस पागलपन में कोई पैटर्न नहीं, कोई रिदम नहीं। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है।उन्होंने यह भी माना कि पिछले दस साल में उनकी सबसे बड़ी सीख यही रही है कि बदलाव को जल्दी अपनाना जरूरी है। उन्होंने बताया, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा यह समझना कि इस समय कौन-सी चीज चल रही है, कौन सी चलनी बंद हो गई और फिर बिना रुके अगली चीज की तरफ बढ़ जाना। प्राजक्ता का मानना है कि डिजिटल स्पेस का सफर जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही रोमांचक भी है। 'मोस्टलीसेन' चैनल से मशहूर हुईं प्राजक्ता 'मिस्मैच्ड' और 'जुग जुग जीयो' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुकी हैं।

शुभांगी को ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

नई दिल्ली/भाषा। अनुपम खेर निर्देशित फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' से अभिनय की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री शुभांगी दत्त ने ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 'तन्वी द ग्रेट' को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी मिला, जिसका श्रेय खेर, अभिषेक दीक्षित और अंकुर सुमन के संयुक्त लेखन को दिया गया।यह कार्यक्रम छह दिसंबर को आयोजित हुआ।शुभांगी ने एक बयान में कहा, ''विश्वास नहीं हो रहा कि यह पुरस्कार जीत लिया और ये बहुत खास अनुभव है। तन्वी के किरदार के लिये ईमानदारी, संवेदनशीलता, अनुशासन और दृढ़ता की मांग की थी, और मैं आभारी हूं कि दुनिया भर के दर्शकों ने इस फिल्म और इसके खूबसूरत संदेश से जुड़ाव महसूस किया। मैं अनुपम सर की बेहद आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण किरदार दिया। यह सम्मान हमारी पूरी टीम का है

पद्म भूषण से सम्मानित अनुपम खेर की निर्देशन में वापसी वाली यह फिल्म एक युवा ऑटिस्टिक महिला (जिसमें दत्त ने भूमिका निभाई है) की भावनात्मक यात्रा और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र - सियाचिन में भारतीय तिरंगे को सम्मान देने के अपने दिवंगत पिता के सपने को साकार करने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। खेर ने कहा, 'शुभांगी इस जीत की पूरी तरह से हक़दार है, क्योंकि उन्होंने तन्वी के किरदार में पूरी ईमानदारी से जान डाल दी। फिल्म में खेर के साथ बोमन ईरानी, पल्लवी जोशी, अरविंद स्वामी, नासर, इयान ग्लेन और करण टैकर भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

पवन सिंह को मिली जान से मारने की धमकी

पटना/एजेन्सी

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को अज्ञात नंबर से फोन कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने 'बिग बॉस 19' में सुपरस्टार सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जान से मिली धमकी के बावजूद पवन सिंह रविवार रात 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे और सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया। उन्होंने 'बिग बॉस' की एक्स कंटेस्टेंट नीलम गिरी के साथ डांस परफॉर्मेंस भी दी। पवन सिंह के मैनेजर ने बताया कि धमकी भरा पहला कॉल 6 दिसंबर की रात लगभग 10 बजे आया। इस कॉल में अज्ञात व्यक्ति ने लगातार धमकियां

देना शुरू कर दिया और पवन सिंह की टीम के सदस्य प्रियांशु को कॉल किया। कॉलर ने पवन सिंह के मैनेजर और टीम के अन्य सदस्यों को लगातार मैसेज भेजे। शुरुआत में कॉलर को यह समझाने की कोशिश की गई कि शायद यह गलत नंबर पर कॉल हो रही है, बावजूद इसके लगातार धमकियां मिलती रहीं। इस धमकी में कॉलर ने पवन सिंह से मोटी रकम की भी मांग की। पवन सिंह के मैनेजर के अनुसार, कॉलर ने 15 से 20 लाख रुपये की डिमांड की और कहा कि यह पैसा जल्द से जल्द जमा करना होगा। साथ ही, कॉलर ने धमकी दी कि अगर पवन सिंह ने सलमान खान के साथ मंच साझा किया, तो उनके साथ वही हाल होगा, जो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के साथ किया था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पवन सिंह की टीम ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को जानकारी दी।

मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कॉल करने वाला कौन था, वह कहां से था, और किस गिरोह से जुड़ा था।

मारवाड़ जंक्शन के मंदिरों के किए दर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। यहां के श्री जिनदत्त कुशल सूरी जैन सेवा एवं संगीत मंडल बसवनगुडी के सदस्य मारवाड़ जंक्शन में विराजित परमात्मा शंखेश्वर पार्श्वनाथ एवं भगवान आदिनाथ के दर्शनार्थ पहुंचे। मंडल के अध्यक्ष अरविन्द कोठारी ने बताया कि चालीस से अधिक वर्ष प्राचीन यह जिनालय है। मंडल के महामंत्री ललित डाकलिया ने बताया कि यहां अत्यन्त ही चमत्कारी परमात्मा पार्श्वनाथ मूलनायक के रूप में विराजमान है और यहां पांच वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित अत्यन्त ही मनोहारी शत्रुंजय गिरिराज की प्रतिकृति और अष्टापद पर्वत की प्रतिकृति मन को लुभाती है।

इसके साथ ही यहां बहुत ही सुन्दर सात्विक भोजन हेतु भोजनशाला भी है। मन्दिर के अध्यक्ष पारस भंडारी, महामंत्री गौतम कटारिया, ट्रस्टी मदन बोहरा ने मंडल के सदस्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम में हितेन्द्र चौपड़ा का सक्रिय सहयोग रहा।

साठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में जिन कुशल सूरी जैन दादावाड़ी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रणजीत ललवानी, मंडल के अध्यक्ष अरविन्द कोठारी, उपाध्यक्ष राकेश डाकलिया, महामंत्री ललित डाकलिया, सहमंत्री धर्मेन्द्र संकलेचा, मोतीलाल ललवानी, सज्जन सिंह खटोड़, गौतमचंद चौपड़ा, शैलेन्द्र डाकलिया, श्री ब्यावर संघ युवा शाखा के महामंत्री कुलदीप छाजेड़, सोहनलाल मेहता, प्रसन्न चंद बाघमार, महावीर चंद सोलंकी, मोहित डाकलिया, कांतिलाल मेहता, अशोक मेहता, अरिहंत पारख, प्रतीक पोफलिया आदि सदस्य उपस्थित थे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माहवारी अवकाश संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाई

बेंगलूरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के लिए महीने में एक दिन का माहवारी अवकाश अनिवार्य किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी।नौ नवंबर को जारी अधिसूचना में 'स्थायी, संविदा और आउटसोर्स' नौकरियों में कार्यरत 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक दिन का सवेतन माहवारी अवकाश देने का प्रावधान किया गया था। न्यायमूर्ति ज्योति एम. की पीठ ने 'बेंगलूरु होटल्स एसोसिएशन' और 'अविराता एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स' द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर यह रोक लगाई। यह अवकाश कारखाना अधिनियम, 1948, कर्नाटक दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961, बागान श्रमिक अधिनियम, 1951, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966 और मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत सभी उद्योगों व प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं के लिए था।

आध्यात्मिक सुखों के समक्ष भौतिक सुख तुच्छ हैं : साध्वी भव्यगुणा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। साध्वीश्री भव्यगुणाजी ने मंगलवार को अपने प्रवचन में कहा कि जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है तो उसे प्रभु की भक्ति में अर्पित कर देना चाहिए। आध्यात्मिक सुखों के समक्ष भौतिक सुख तुच्छ होते हैं। जिनवाणी हमें आध्यात्मिक सुख पाने का मार्ग दिखाती है। जिनवाणी श्रवण कर उसे जीवन में उतारने वाले को भौतिक सुखों में आनंद महसूस नहीं होता और वह तप, त्याग व साधना के मार्ग पर बढ़ता जाता है। जिनवाणी चंचल मन को एकाग्र बना साधना व स्वाध्याय से जोड़ने का कार्य करती है। जब भी मन अशांत हो तब जिनवाणी व धर्म की शरण लेनी चाहिए, शांति की अनुभूति होगी।ङ्कङ्कसाध्वी शीतलगुणाजी ने कहा कि जीवन धर्म साधना व आराधना के लिए होता है। धर्म साधना में तीन तत्व तन का रोग, इन्द्रियों का भोग ओर मन का लोभ बाधक बनते हैं। अज्ञान व इन्द्रिय भोग की वृति से तन का रोग उत्पन्न होता है। अज्ञानता दूर कर इन्द्रिय निग्रह कर हम स्वस्थ बने रह सकते है। उन्होंने कहा कि इन्द्रियों पर नियंत्रण रखने पर तन स्वस्थ ओर मन प्रसन्न रहता है। ऐसा किए बिना हम धर्म आराधना ओर तप त्याग नहीं कर सकते है। धर्म साधना के लिए तन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कियुद्ध जीत लेने वाला विजेता नहीं होता है बल्कि वास्तविक विजेता तो वह होता है जो अपने दुगुणों व इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि हम अपना यह भव व आगे के भव सुधारना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्य सांसारिक लड़ाइयां जीतना नहीं बल्कि अपने कषायों व इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना होना चाहिए।

बिड़दी में मनाया आचार्यश्री तुलसी दीक्षा शताब्दी समारोह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। यहां आचार्यश्री महाश्रमणजी की शिष्या साध्वीश्री पुण्ययशाजी के सान्निध्य में आचार्य श्री तुलसी के दीक्षा शताब्दी समारोह का आयोजन बिड़दी स्थित ईमरतलाल देवड़ा के निवास पर हुआ। नमस्कार महामंत्र एवं तुलसी अष्टकम द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। साध्वीश्री ने कहा कि आचार्य तुलसी विशेष लक्षण के धनी थे, उस लाल को पहचाना आचार्य कालू ने।आचार्य तुलसी का जीवन विलक्षण, क्रान्तिकारी था। उन्होंने श्रावक-श्राविकाओं, साधु-साध्वियों के जीवन का आध्यात्मिक विकास किया। वे विकास की पर्याय थे। आचार्यश्री महाप्रज्ञजी ने आप द्वारा प्रदत्त विकास के आयामों को देखकर आपके पट्ट महोत्सव को विकास महोत्सव का रूप दिया। आपका जीवन युगप्रधान था। आपने युगीन समस्याओं का समाधान दिया। आचार्य तुलसी का जीवन पारस मणि के समान है जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बनता है। वैसे ही आपके चरणों में आने वाले का जीवन स्वर्णिम बन जाता है। आचार्य तुलसी का जीवन एक प्रयोगशाला था जिसका फलित है जीवन विज्ञान, प्रेक्षाध्यान। आचार्यश्री इसी प्रायोगिकता को और शत्गुणित कर रहे हैं। राजराजेश्वरी नगर के सभाध्यक्ष राकेश छाजेड़, बिड़दी उपसभा के अध्यक्ष कुशल देवड़ा, अभातेमम से मधु कटारिया, आचार्य तुलसी के संसार पक्षीय पौत्र पद्म खटेड़ एवं परिवार की बहनों सहित अनेक वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। साध्वी वर्धमानयशाजी, बोधिप्रभाजी द्वारा आचार्य तुलसी जीवन-यात्रा पर आधारित शब्द-चित्र की रोचक प्रस्तुति दी गई। मंच संचालन साध्वी विनितयशाजी ने किया। कार्यक्रम में राजराजेश्वरी नगर, मंड्या, बिड़दी से श्रावक समाज की अच्छी उपस्थिति रही।

सिद्दरामय्या ने अरहर दाल की एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दो केंद्रीय एजेंसियों के जरिये अरहर दाल की एमएसपी पर खरीद के लिए तुरंत मंजूरी देने का आग्रह किया है। उन्होंने राज्य के प्रमुख खरीद केंद्रों पर इनके संचालन की व्यवस्था शीघ्र प्रभाव से कराने का भी आग्रह किया है ताकि फसल की अधिकतम आमद शुरू होने से पहले ही खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर किसी भी प्रकार की देरी से किसानों में असंतोष पनप सकता है और कीमतों में गिरावट हो सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी को आठ दिसंबर को लिखे और मंगलवार को मीडिया के साथ साझा किए गए एक पत्र में सिद्दरामय्या ने याद दिलाया कि कर्नाटक सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से अरहर दाल की एमएसपी आधारित खरीद के लिए तत्काल मंजूरी को लेकर एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कहा, हालांकि, हम अभी भी केंद्र सरकार के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि बाज़ार में आवक तेज़ी से बढ़ रही है। पत्र में, सिद्दरामय्या ने कहा कि चालू खरीफ़ सीज़न (2025-26) के दौरान, कर्नाटक में लगभग 16.80 लाख हेक्टेयर में अरहर दाल की फसल बोई गई है, जिसका उत्पादन 12.60 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि यह फसल कलबुर्गी, यादगीर, बीदर, रायचूर, विजयपुर, कोप्पल, बेलगावी, बेल्लारी, विजयनगर, बागलकोट, कोलार, चिक्कबल्लापुर और चित्रदुर्ग सहित प्रमुख उत्पादक जिलों के किसानों की आय की रीढ़ है।

सिद्दरामय्या के अनुसार, वर्तमान में, आदर्श बाजार मूल्य 5,830 रुपये से 6,700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है, जबकि 2025-26 के लिए अरहर दाल को लेकर घोषित एमएसपी लगभग 28,000 रुपये प्रति क्विंटल है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच अधिकतम आवक की उम्मीद है, लेकिन केंद्र सरकार खरीद केंद्र केवल फरवरी और मार्च में ही खोलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किए जाने से किसानों को आय संबंधी गंभीर झटका लग सकता है।

मैसूरु जीतो ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर का किया सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। यहां मंगलवार को मैसूरु जीतो द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी की नवनियुक्त डायरेक्टर उषा कुमारी का स्वागत अभिनंदन किया गया। जीतो के पदाधिकारियों द्वारा शहर में अतिरिक्त विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में बताया गया कि मैसूरु पर्यटन एवं व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। लेकिन हवाई आवागमन की ज्यादा सुविधाएं नहीं होने की वजह से पर्यटन एवं वाणिज्यिक गतिविधियों ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। पदाधिकारियों ने डायरेक्टर के साथ एक बैठक कर और अन्य सुझाव व विचार व्यक्त किए। इस मौक़े पर जीतो मैसूरु के चेयरमैन विनोद बाकलीवाल, वाइस चेयरमैन भेरूलाल पितलिया, मुख्य सचिव गौतम सालेचा, सचिव प्रेम पालरेचा, रमेश नवलखा, लेडीज़ विंग मुख्य सचिव रजनी डाकलिया आदि उपस्थित थे।

हिंदी में रोजगार के अवसर पर विशेष व्याख्यान हुआ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। यहां कोतनूर के नारायणपुरा स्थित क्रिस्तु जयंती विश्वविद्यालय में 9 दिसम्बर को बेंगलूरु के हिंदी अध्ययन विभाग द्वारा 'हिंदी में रोजगार के अवसर' विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहायक निदेशक डॉ. दीपक पाण्डेय उपस्थित रहे। उन्होंने अपने व्याख्यान में हिंदी भाषा के अकादमिक व व्यावसायिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि आज हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहकर सूचना-प्रौद्योगिकी, अनुवाद, मीडिया, राजभाषा, पर्यटन, कंटेंट निर्माण और ई-लर्निंग जैसे अनेक क्षेत्रों में विशाल रोजगार अवसर प्रदान कर रही है।

उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में हिंदी कंटेंट की मांग निरंतर बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप पत्रकारिता, तकनीकी लेखन, अनुवाद, प्रकाशन, संपादन और सरकारी विभागों में हिंदी विशेषज्ञों की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है। उन्होंने मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं, प्रशिक्षणों तथा हिंदी के संवर्धन हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी छात्रों को दी।

इस अवसर पर हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. श्रीधर पी. डी. सहित विभाग के प्राध्यापक डॉ. विनोद बाबूराव मेघश्याम, डॉ. मोहम्मद नयाज़ पाशा, डॉ. मुस्लिम अब्दुल रजाक और डॉ. गणशेटवार साईनाथ नागनाथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक डॉ. बेंद्रे बसवेश्वर नागोराव ने किया। विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से सहभागिता लेते हुए रोजगार की संभावनाओं के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे, जिनका मुख्य वक्ता द्वारा समाधान प्रदान किया गया। अंत में विभागाध्यक्ष ने डॉ. दीपक पाण्डेय का आभार व्यक्त कर स्मृति चिह्न भेंट किया। संपूर्ण व्याख्यान ज्ञानवर्धक तथा विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुआ।

वितरण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु के मागड़ी रोड चोल्युळपाल्या स्थित जय भीम एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सोमवार को आयोजित एक समारोह में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री एवं जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी का वितरण करते हुए मुख्यअतिथि राजनेता एच रविन्द्र, गौसेवक महेन्द्र मुणोत एवं ट्रस्ट के प्रसाद, श्रीधर एवं अन्य।

देवेगौड़ा ने सरकार को राष्ट्र गीत वंदे मातरम् को 150 गायन शैली में रिकार्ड करने का सुझाव दिया

नई दिल्ली/बेंगलूरु। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने मंगलवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार को सुझाव दिया कि राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे 150 विभिन्न गायन शैली में रिकार्ड करवाया जाना चाहिए। उच्च सदन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा में भाग लेते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि वंदे मातरम ऐसा गीत है जिसने भारतीय की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे भले ही बांग्ला में लिखा था किंतु इसमें इतने संस्कृत शब्द हैं कि इसे देश के अन्य भागों में आसानी से अपना लिया गया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार को सुझाव दिया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस गीत को 150 विभिन्न गायन शैलियों, संगीत और परंपरा के अनुसार गवाया जाए और रिकार्ड किया जाए। देवेगौड़ा ने कहा कि इस गीत की आत्मा ने देश को पूर्व में ही नहीं, आज भी एकजुट कर रखा है। उन्होंने कहा कि इतने गीत लिखे गये किंतु कुछ ही गीत ऐसे होते हैं जो देश को छू जाते हैं और उसका कारण उनके शब्द नहीं, बल्कि गाने की आत्मा होती है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, उसी तरह इस गीत की आत्मा शाश्वत है। उन्होंने इस अवसर पर कर्नाटक राज्य के गीत का भी जिक्र किया। देवेगौड़ा ने कहा कि भारत में आज जितने भी राज्यों के गीत हैं, वे वंदे मातरम से प्रेरित होकर लिखे गये हैं।

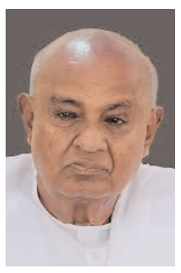

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

नवगीत

यादों के साये में

यादों के साये में जीवन बीत रहा है।
थकती साँसों से हर लम्हा जीत रहा है।।

जोड़ा करते थे हम कल तक पाई-पाई
रोज़ लगाते हैं अब रिश्तों में तुरपाई।
खुशियों का घट धीरे- धीरे रीत रहा है।।

संबंधों में पहले जैसी बात नहीं हैं
कड़ुवाहट है बातों में सौगात नहीं है।
दूर हो रहा है जो सालों मीत रहा है।।

बाँधा करते थे जिसको अपने छंदों में
बैठे दिखता है अब वो भी छलछंदों में।
बंधनमुक्त हुआ जो मेरा गीत रहा है।।

■ माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग'
मो. 9424141875

कर्नाटक को तीन साल में साइबर धोखाधड़ी में 5,474 करोड़ रुपये का नुकसान : मंत्री

बेंगलूरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य के लोगों को साइबर धोखाधड़ी में 5,474 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जिसमें से पुलिस अब तक 627 करोड़ रुपये वसूलने में कामयाब रही है। मंत्री विधानसभा में सकलेशपुर से भाजपा विधायक सीमेंट मंजू के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। परमेश्वर ने कहा, ''हाल के दिनों में साइबर धोखाधड़ी बढ़ी है। पिछले चार वर्षों में कर्नाटक में साइबर धोखाधड़ी के लगभग 52,000 मामले हुए हैं और यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।''

उन्होंने बताया कि सरकार ने पुलिस कानूनों में संशोधन करके साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने की योजना बनाई है। हालांकि 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' ने इस संशोधन पर अदालत से स्थगन प्राप्त कर लिया है और यह मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा, ''यह मामला 19 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध है।''

परमेश्वर ने कहा कि 2023 में साइबर धोखाधड़ी के 22,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिससे 873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जिसमें से 177 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

इंडिगो ने बेंगलूरु और हैदराबाद से करीब 180 उड़ान रद्द कीं

बेंगलूरु/मुम्बई/दक्षिण भारत। इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान आठवें दिन भी जारी रहा और विमानन कंपनी ने मंगलवार को बेंगलूरु तथा हैदराबाद से करीब 180 उड़ानें रद्द कर दीं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा, इंडिगो मंगलवार को हैदराबाद आने-जाने वाली 58 उड़ानों का संचालन नहीं करेगा, जिसमें से पहुंचने वाली 14 और रवाना होने वाली 44 उड़ानें हैं। उन्होंने बताया कि बेंगलूरु हवाई अड्डे पर रद्द की गई उड़ानों की संख्या 121 है, जिनमें से पहुंचने वाली 58 और रवाना होने वाली 63 उड़ानें हैं। इस बीच, कुछ मार्गों पर शीतकालीन कार्यक्रम की इंडिगो की उड़ान अन्य घरेलू विमानन को दी जाने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि सरकार इंडिगो के 'स्लॉट' में ''निश्चित रूप से'' कटौती करेगी। राहुल भाटिया द्वारा नियंत्रित विमानन कंपनी 90 से अधिक घरेलू स्थलों और 40 से अधिक विदेशी स्थलों से प्रतिदिन 2,200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है।

नायडू ने सोमवार को दूरदर्शन समाचार चैनल से कहा, ''हम निश्चित रूप से इंडिगो के (शीतकालीन) कार्यक्रम में कटौती करेंगे।

इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। वे उन (कटौती किए गए) मार्गों पर उड़ान नहीं भर पाएंगे और यह विमानन कंपनी पर एक तरह का जुर्माना होगा।'' उन्होंने कहा कि इंडिगो के शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम (शेड्यूल) में कटौती करने के बाद उन्हें दूसरी विमानन कंपनियों को आवंटित कर दिया जाएगा। गुरुग्राम स्थित विमानन कंपनी भारत की कुल घरेलू उड़ानों का 65 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संभालती है और इसने सोमवार को छह हवाई अड्डों से 560 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com/**RNI No. 58061/93.**